● वर्ष-3
● अंक-290
रायपुर, रविवार
14 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› मैं मिल रहे रिस्पॉन्स से थोड़ी चकित..

जो अंतिम पंक्ति पर हैं, उनको प्राथमिकता -मोदी

मुंबई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया। इस अबसर पर उन्होंने कहा कि आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 3 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट्स से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है।

मोदी ने कहा कि इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा। 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी है। 76 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीते 1 महीने से मुंबई देश-विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता और स्थायित्व दे सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार तीन गुना तेजी से काम करेगी और आज ये होते हुए हम देख रहे हैं।

मुंबई के प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण

नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है। महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है। महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वो राज्य है, जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं - भारत की आकांक्षाओं इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब-करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है, अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में महाराष्ट्र में नेशनल हाइवे की लंबाई बढ़कर तीन गुना हो चुकी है। गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का शानदार उदाहरण है। कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है, तो उससे महिलाओं को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान भी मिलता है। यानी एनडीए सरकार के ये काम गरीब, किसान, नारीशक्ति और युवाशक्ति को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही, हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों का मुंह बंद कर दिया है। ये लोग निवेश, बुनियादी ढांचे और देश के विकास का विरोध करते हैं और अब बेनकाब हो रहे हैं। देश के नागरिक उनकी साजिशों को खारिज कर रहे हैं।

नयी दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से शनिवार को मुलाकात की। सोरेन ने कांग्रेस नेता के आवास से निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा कि जेल से बाहर आने के बाद यह उनकी एक शिष्टाचार भेंट थी और इस मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।

उपचुनाव के नतीजों पर बोले जयराम

देश के राजनीतिक माहौल में बदलाव की प्रतीक है कांग्रेस की जीतः रमेश

नई दिल्ली। देश में हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को जारी हुए हैं। नतीजों में हिमाचल प्रदेश और भाजपा शासित उत्तराखंड में अपनी जीत की कांग्रेस ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी चालें बुरी तरफ विफल हुई हैं। यही नहीं अब देश में राजनीतिक माहौल बदलने लगा है। उपचुनाव के नतीजे ये स्पष्ट तौर पर दर्शा रहे हैं।

बुधवार को पंजाब में 1, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 1 और तमिलनाडु में 1 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश और भाजपा शासित उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनावों में अपनी जीत की सराहना की। उत्तराखंड में पार्टी की जीत पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मंगलौर को बसपा से छीना गया और भाजपा की गंदी चालों का सामना करना पड़ा। वहीं बद्रीनाथ में मौजूदा विधायक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन उनके इस फैसले को लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सही सजा दी है और कांग्रेस ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उन्होंने नतीजों की सराहना करते हुए कहा, दोनों तरह से नतीजे देश में बदलते राजनीतिक माहौल को दर्शाते हैं।

वहीं हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर रमेश ने कहा कि भाजपा की सारी चालें बुरी तरह विफल हो गई हैं।

उन्होंने कहा, ऑपरेशन लोटस के तहत निर्दलीयों को लुभाकर लाए गए दो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यह जीत कांग्रेस की महत्वपूर्ण वापसी और भाजपा के प्रति जनता की नाराजगी को स्पष्ट तरीके से दर्शाता है।

टूट चुका है भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल

सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर इंडिया ब्लॉक की जीत दर्ज होने के बाद कांग्रेस गदगद है। इसी को लेकर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट गया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया 'भय और भ्रम' का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मज़दूर, व्यापारी और नौकरीपेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल ने आगे लिखा कि अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है।

'स्पाइवेयर' अटैक के बाद वेणुगोपाल ने मोदी को कहा थैंक्स

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि उन्हें एप्पल से एक धमकी भरा नोटिफिकेशन मिला है जिसमें बताया गया है कि उन्हें एक भाड़े के स्पाइवेयर का उपयोग करके निशाना बनाया जा रहा है जो उनकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन से समझौता करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि उन्हें भेजी गई धमकी की अधिसूचना में लिखा है कि उन्हें 30 अक्टूबर, 2023 को भी सूचित किया गया था और यह उनके डिवाइस के खिलाफ एक और हमला था। वेणुगोपाल द्वारा ट्वीट किए गए अधिसूचना के स्क्रीनशॉट में कहा गया है एप्पल ने पहले आपको 30 अक्टूबर, 2023 को एक अधिसूचना भेजी थी। यह कोई दोहराई गई सूचना नहीं है। यह आपको सूचित करने के लिए है कि हमने आपके डिवाइस के खिलाफ एक और हमले का पता लगाया है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) और केरल के अलाप्पुझा से संसद सदस्य (सांसद) वेणुगोपाल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी और संस्थापक इल्तिजा मुफ्ती के बाद इस तिमाही में एप्पल से यह त्रैमासिक अधिसूचना प्राप्त करने वाले कम से कम तीसरे व्यक्ति हैं।

रायपुर। अयोध्या धाम में पवित्र राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में नारा गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। (विस्तृत समाचार पेज 3 पर)

शिक्षक से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हैः सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के प्रयास के बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने दिल्ली के 5004 शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को रोकने का काम किया है जिसके बाद राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ ने आज एनडीएमसी हाल में एक सम्मान समारोह के दौरान सचदेवा के साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और बांरी स्वराज को सम्मानित किया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शिक्षक से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और हमेशा आपसे कुछ सीखने को मिलता है।

प्रमुख समाचार

केजरीवाल के जमानत पर बोले सचदेव पुराना रटा रटाया बयान

नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सांसद संजय सिंह का अरविंद केजरीवाल की जेल, जमानत और स्वास्थ्य से संबंधित बयान कुछ नया नहीं बल्कि पुराना रटा रटाया बयान है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत की कोई उम्मीद नजर आती है, तो वे अपना पुराना बयान दोहराने लगते हैं कि बीजेपी केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका वजन घट रहा है और गंभीर बीमारी की संभावना है। संजय सिंह को याद करना चाहिए कि जब भी केजरीवाल को जमानत मिलती है, वह कभी भी इलाज के लिए नहीं जाते बल्कि उनकी राजनीतिक टिप्पणियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि संजय सिंह को ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अब कोई विश्वास नहीं रह गया है, जैसा कि उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनावों में केजरीवाल की जेल का जवाब वोट से अभियान को खारिज करके दिखाया। केजरीवाल ने बार-बार मतदाताओं से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र रहूं तो मुझे वोट दें, लेकिन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के लोगों ने केजरीवाल और उनकी अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

राहुल की मनाही के बाद भी अंबानी के मेहमान बने कांग्रेसी

मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बॉलीवुड सेलेब्स के बाद कई राजनेता भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को विवाह स्थल पर पहुंचे। अनंत और राधिका की शादी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अपने पति के साथ शामिल हुईं। शादी समारोह के रेड कार्पेट पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद भी नजर आए। मुंबई में हुई शादी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही योगगुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

आंध्र प्रदेश में विकास का श्रेय लेने की सियासी जंग

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में श्रेय लेने की जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का श्रेय लिया। विशाखापत्तनम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमरनाथ ने नायडू पर मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राज्य के अन्य क्षेत्रों की अनदेखी करते हुए केवल राजधानी क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। पिछले वाईएसआरसी शासन के दौरान भोगापुरम हवाईअड्डा परियोजना कार्यों में तेजी आई। पिछले टीडीपी शासन ने परियोजना के लिए कुल 2,200 एकड़ में से केवल 377 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। वाईएसआरसी सरकार ने परियोजना को गति देने के लिए स्थानीय किसानों के साथ परामर्श के माध्यम से 1,900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। उन्होंने बताया कि वाईएसआरसी शासन के दौरान हवाईअड्डा परियोजना का लगभग 35% काम पूरा हो गया था।

रुपाली विस उपचुनाव के नतीजे में राजद को मिली हार

नई दिल्ली। बिहार में हुए एकमात्र उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। दरअसल, पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली रूपाली विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव हुआ था। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मार ली है। लेकिन मुख्य मुकाबला जदयू और राजद के बीच ही माना जा रहा था। जदयू ने जहां कलाधर मंडल को मैदान में उतारा था। तो वहीं राजद ने लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद भी बीमा भारती पर भरोसा बनाए रखा। जदयू से नाराजगी के बाद बीमा भारती राजद में शामिल हो गई थीं। उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं सकी थीं। वह रूपाली से पूर्व विधायक रही हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद ही यह विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर रुपौली में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तेजस्वी यादव की हर कैसे हुई? क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी से बदला ले लिया? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे।

सिंधिया और हिमंत ने असम में दूरसंचार सेवाओं पर चर्चा हुई

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योदिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ बैठक की और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार समेत राज्य में विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। सिंधिया ने सुबह शर्मा के साथ बैठक की और अपनी चर्चा को सार्थक बताया। उन्होंने असम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सिंधिया शुक्रवार से पूर्वोत्तर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''(हमने) उन संभावना वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जहां दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है ताकि और 'संपर्क संपन्न एवं डिजिटल असम' की ओर बढ़ा जा सके।'' शर्मा ने भी 'एक्स' पर इस बैठक के बारे में लिखा और कहा कि उन दोनों के बीच 4जी, 5 जी और उच्च रफ्तार वाली इंटरनेट सेवाओं का विस्तार बढ़ाकर असम में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार लाने समेत विभिन्न विषयों पर अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने दूरसंचार बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने तथा बाढ़-संभावित क्षेत्रों में शीघ्र नेटवर्क बहाली के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की रणनीतियों पर भी चर्चा की। मंत्रियों ने पूर्वोत्तर परिषद के साथ तालमेल में सुधार लाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर भी चर्चा की।

उप चुनाव नतीजे : विपक्ष के लिए संजीवनी तो भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय

विनोद पाठक

सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उप चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 10 सीटें इंडी एलायंस के खाते में गई हैं, जबकि भाजपा को केवल दो और एक निर्दलीय को मिली है। सबसे अधिक घाटा भाजपा को पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल के नतीजे यह दर्शा रहे हैं कि जो बढ़त भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, वो अब खत्म हो गई है।

उप चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस ने न केवल अपनी जमीन को बचाया, बल्कि कुछ बढ़ोतरी भी हासिल की। वैसे तो इन नतीजों से किसी भी राज्य की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगास लेकिन लोकसभा के बाद इन उप चुनावों पर देश की नजर जरूर थी। निश्चित ही भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय है।

पहले चर्चा पश्चिम बंगाल की। यहां चार सीटों पर उप चुनाव हुआ। चार में से तीन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती थी, जबकि एक सीट तृणमूल कांग्रेस के पास थी। लोकसभा चुनाव की भांति तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा है। तीन सीटें रानाघाट दक्षिण, रायगंज और बागदा भाजपा से छीन ली हैं, जबकि मानिकतला को बरकरार रखने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब रही है।

लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस को घेरा था और ममता बनर्जी पर तीखे आक्रमण हुए थे, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता पर हिंसा को लेकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है।

हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट भाजपा ने जीती है, जिस पर पहले निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा था। हिमाचल की बाकी दोनों सीटें

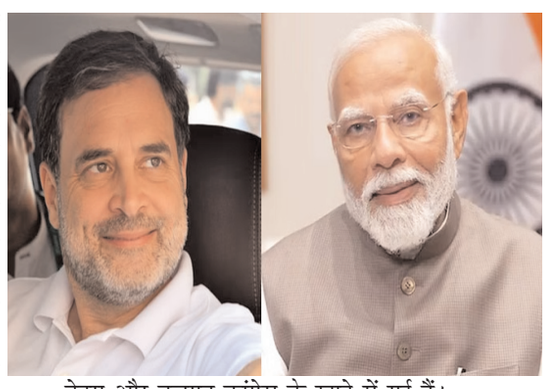

देहरा और नलगढ़ कांग्रेस के खाते में गई हैं। यहां भाजपा दूसरे स्थान पर रही है, जबकि यह दोनों सीट पहले निर्दलीय के पास थीं। अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की सभी चारों सीटों पर जीत का परचम लहराया था।

ऐसे में कांग्रेस ने दो सीट जीतकर वापसी की है। हालांकि, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ध्यान विधानसभा उप चुनाव पर ही था, क्योंकि कांग्रेस सरकार संकट में आ गई थी। इन नतीजों से कांग्रेस को राहत मिली है।

उत्तराखंड में भी दो सीटों पर उप चुनाव था। हालांकि, यह दोनों बद्रीनाथ और मंगलौर सीट सत्तारूढ़ भाजपा के पास नहीं थी। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट पुनः जीत ली है। वैसे, सोशल मीडिया पर इस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा है।

मंगलौर की सीट को कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से छीना है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में एक सीट की बढ़त बना ली है। बद्रीनाथ सीट को भावनात्मक रूप से देखा जा रहा था। यहां भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दोनों ऐसे राज्य हैं, जहां अग्निवीर योजना का एक बड़ा मुद्दा है।

बिहार में भाजपा के सहयोगी जनता दल (यू) को झटका लगा है। रूपौली सीट पर जनता दल (यू) के प्रत्याशी की हार हुई है, जबकि यहां से पप्पू यादव समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया है। पप्पू यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। भले यहां आरजेडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, लेकिन पप्पू यादव के निर्दलीय उम्मीदवार को इंडी एलायंस का ही एक हिस्सा मानना चाहिए।

तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए जालंधर पश्चिम की सीट एक प्रतिष्ठा का विषय बन गई थी। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर पूरा जोर लगाया हुआ था। हालांकि, यह सीट पहले भी आम आदमी पार्टी के पास ही थी। यहां भाजपा ने दूसरे नंबर पर रहकर यह बताया है कि पंजाब में उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश से भाजपा के लिए थोड़ी अच्छी खबर आई, क्योंकि यहां की अमरवाड़ा सीट, जो पहले कांग्रेस के पास थी, उसे पार्टी ने जीत लिया है, यानी राज्य में उसकी सीटों में एक सीट का इजाफा हो गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु की विक्रवड़ी सीट को डीएमके ने बरकरार रखा है।

कांग्रेस और इंडी एलायंस के लिए यह उप चुनाव नतीजे संजीवनी का काम करेंगे। विपक्ष को नई धार मिली है। खासकर अक्टूबर में होने जा रहे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष निश्चित रूप से उत्साहित होगा। विपक्ष के लिए यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एकजुट होकर वो भाजपा को हरा सकता है। यही रणनीति आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगी।

भाजपा के लिए निश्चित रूप से आत्ममंथन का समय है। भले यह नतीजे उसकी सरकारों पर बहुत अधिक प्रभाव न डालें, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरता ही है। जनता के बीच ऐसी धारणा बनती है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी से लोगों का मोहभंग हो रहा है।

छिंदई नदी में बना उच्च स्तरीय पुल, ग्रामीणों के लिए खुल गया आवागमन का रास्ता

■ परेशानियों को दूर करने के साथ रिश्तों को भी मजबूत बना रहा पुल

कोरबा/रायपुर। बारिश के साथ ही उफान पर रहने वाले मदवानी के इस छिंदई नदी को पार कर पाना आसपास के ग्रामीणों के लिए कितना जोखिम भरा होता था, यह तो ग्रामीण ही जानते हैं। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या फिर अपने किसी परिचित के घर जाना हो, लंबे समय तक पुल नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ता था। बारिश आते ही महीनों तक बहुत से लोगों की या तो भेंट मुलाकात बंद हो जाती थी, या फिर लंबी दूरी तय कर एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। इस लंबी दूरी को तय करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे तो खर्च करने ही पड़ते थे, इसके साथ ही बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ता था। अब जबकि इस छिंदई नदी में पुल बन गया है, ग्रामीणों का आवागमन आसान बन गया है। वे आसानी से घंटों की दूरी मिनटों में तय कर पहुंच जाते हैं।

करतला विकासखंड के ग्राम मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में लगभग 17 करोड़ 17 लाख की राशि से बने उच्च स्तरीय पुल का हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव ने लोकार्पण किया था। रामपुर, मदवानी सहित आसपास के अनेक गांव को कुदमुरा, हाटी सहित प्रमुख मार्गों से जोडऩे में यह पुल ग्रामीणों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गाँव जुड़ गए हैं। एक दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ गया है। यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल बन गया है।

इस पुल को पार करते हुए ग्रामीण कमल सिंह चौहान ने बताया कि पहले उन्हें लंबी दूरी तय करके एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उन्हें पांच से 10 किलोमीटर अतिरिक्त वाहन बाइक घुमाना पड़ता था। इससे उनके अतिरक्त रूपये और समय का नुकसान होता था। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में नदी में पानी कास्तर कम होने पर बहुत से ग्रामीण जोखिम उठाकर नदी पार कर लेते थे। बारिश में नदी का स्तर बढऩे पर पुल पार करना खतरनाक बन जाता था। अब जबकि पुल बन गया है। आवागमन में आसानी होने के साथ ग्रामीणों को बहुत सहूलियत होने लगी है। ग्राम मदवानी के किसान श्री भुनेश्वर राठिया का कहना है कि गांव में रहने वाले लोगों का दूसरे गांव तक रिश्तेदारों के पास सुख-दुख में आना-जाना रहता है। पुल नहीं होने से विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए कुछ लोग जोखिम उठाकर पुल पार करने की कोशिश करते थे, वहीं कुछ लोग अपना बहुत समय बर्बाद कर दूसरे रास्तों से आवागमन करते थे।

इस पुल से मदवानी, कछार, महराजगंज, चारमार, रामपुर, कुदमुरा, करतला, चांपा सहित अन्य गांव के ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि आसपास के गांव में लड़के-लड़कियों की शादी तय होती है और रिश्ते बनते हैं। ग्राम मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग के छिंदई नदी में पुल सिर्फ आवगमन का पुल ही नहीं है। यह पुल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने वाले और हमारी परेशानियों को दूर करते हुए खर्च को कम कर खुशियां देने वाला पुल भी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में कोरबा जिले में दूरस्थ एवं पहुंच विहीन क्षेत्रों में तथा आवश्यकतानुसार नदी नालों में आवागमन हेतु पुल निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने भी आवागमन हेतु ऐसे स्थानों को चिन्हित करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देष दिए हैं, जहां पुल निर्माण की आवश्यकता है।

बोर्ड पर गुणवत्तायुक्त सड़क का दावा लेकिन धरातल पर स्थिति विपरीत

पहली बारिश में उधड़ गई सड़क

मुंगेली। मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए कमाई का जरिया बन गया है, यह बात हम नहीं, बल्कि ग्रामीण कह रहे हैं। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क पहली ही बारिश में उधड़ने लगी है।

मुंगेली जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ञ्07 यानी मुंगेली-पंडरिया मुख्य मार्ग से गोपातपुर तक सड़क संधारण कार्य चल रहा है। लगभग 1300 मीटर के इस कार्य की शुरुआत जुलाई 2023 में की गई थी, जिसे अप्रेल 2024 तक पूर्ण करना था। ग्रामीणों ने बताया कि मेकडम मेकर्स द्वारा 37 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनाए गए सड़क की गुणवत्ता से समझौता हुआ है।

स्थानीय लोगों कि माने तो सड़क संधारण में शुरू से ही मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसका नतीजा रहा कि निर्माण होते-होते ही सड़क अपनी स्थिति बयां कर रही है। सड़क कहीं पूरी तरह से उखड़ गई है, तो कहीं बीच-बीच में गड्ढे देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी पर कई बार आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर दिया, जिसका नतीजा सामने है। सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। जगह-जगह विकराल गड्ढे दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे है।

ग्रामीण बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाए गए सड़क पर मानक को ताक में रखकर ठेकेदार मनमाने तरीके से निर्माण कराया है। पहली बारिश में सड़क के ऐसे हालात है तो आगे क्या स्थिति होगी। इस खराब रोड की वजह से गांव से मुख्य सड़क मार्ग आना-जाना मुश्किल हो जाता है। यह मामला गंभीर विषय है जिसे जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभारी कार्यपालन अभियंता बीएल सिंहस्त्रे ने मामले को लेकर बताया कि कार्य प्रगतिरत है। ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया है। कार्य में अगर लापरवाही की गई है तो इसकी जांच करवाकर इसपर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बने सड़कों के रख रखाव व दुरुस्तीकरण का जिम्मा पांच वर्ष तक कार्यदायी संस्था का होता है। गौर करने वाली बात यह है कि मार्ग पर लगे बोर्ड पर मानक व लागत का उल्लेख तो किया गया है, पर उसके अनुरूप बन रहा है यह जांच होने पर स्पष्ट हो सकेगा। लाखों की लागत से बन रही सड़क 15 दिनों में ही उखड़ गई है, जो मानकों पर सवाल खड़ा करता है। वैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़त योजना विभाग गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की बात करती है, लेकिन धरातल पर गुणवत्ता हवा हवाई क्यों हो जाती है।

बनने से पहले गायब हो गया प्राथमिक शाला भवन

■ बच्चों का भविष्य संवारने बेवा ने दे दिया अपना पीएम आवास

गरियाबंद। जर्जर स्कूल भवनों के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, इनमें घूम-फिर के बात आखिरकार भ्रष्टाचार, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता सामने आती है। ऐसा ही वाकया गरियाबंद जिले में एक प्रायमरी स्कूल का है, जो कागजों में तो सरकारी भवन में संचालित होता नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक बेवा के पीएम आवास में संचालित है, जिसने जर्जर भवन में बच्चों की भविष्य खतरे में देख अपना पीएम आवास सौंपकर झोपड़ी में रहना मंजूर किया है।

बात हो रही है मैनपुर ब्लॉक के मूड़ागांव में चचरा पारा स्थित प्राथमिक स्कूल की, जिसका संचालन बेवा गुनो बाई के पीएम आवास में बीते तीन सालों से हो रहा है। हैरानी की बात है कि सिस्टम पर गुनो बाई के इस करारे तमाचा के बावजूद किसी जिम्मेदार ने 22 बच्चों वाले इस स्कूल की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। गुनो बाई का एक बेटा है, जिसके साथ वह बस्ती के भीतर अपनी पुरानी झोपड़ी में रह रही है। गुनो बाई कहती है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं। जर्जर भवन वाले स्कूल में खतरा देखते हुए उसने अपने आवास को स्कूल संचालन के लिए दे दिया।

गांव के पंच कपूर चंद मांझी जिम्मेदारों के एक और करतूत के बारे में खुलासा करते हुए बताते हैं कि 1997 में बने भवन में स्कूल संचालित हो रहा था। मांग के बाद 2006 में नए स्कूल भवन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 4।18 लाख की स्वीकृति मिली, भवन का जिम्मा पंचायत और मास्टर जी के जवाबदारी में बन रहा था। नींव और प्लिंथ खड़े हुए फिर अचानक से काम बंद हो गया। आज 10 साल बाद भवन का नामोनिशान तक नहीं है। पंच ने कहा कि नए भवन की मांग करने जाते हैं, तो रिकार्ड में भवन दिखता है इसलिए नए भवन नही मिला।

तमाम कोशिश के बीच जब पिछली सरकार के स्कूल जतन योजना के भवन मरम्मत की सूची में जब चचरापारा का नाम आया तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 1997 के जर्जर भवन के मरम्मत के लिए 10 लाख से ज्यादा की मंजूरी मिली थी, लेकिन यह काम भी प्रशासन नहीं करा पाया। बता दे कि मैनपुर ब्लॉक में 267 स्कूल भवन को जतन योजना के लिए चयन किया गया था, लेकिन सालभर में आरईएस विभाग केवल 66 भवन ही मरम्मत करा पाया। चचरापारा प्राथमिक शाला भवन के हालात से अनजान मैनपुर आरईएस एसडीओ उमेस चौधरी कहते हैं कि टेंडर जारी हुए थे, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थिति के चलते आधा से ज्यादा काम शुरू नहीं हो सके। स्कूल जतन योजना में गरियाबंद को 90 करोड़ दिया गया है। 1300 स्कूल भवनों की मरम्मत की जानी थी, लेकिन साल भर में 550 भवनों की ही मरम्मत हो पाई है। हैरानी की बात है कि खर्च का लेखा-जोखा शिक्षा विभाग देख रहा है, और काम की जिम्मेदारी आरईएस विभाग के पास है, लेकिन दोनों मिलकर स्कूलों के जतन में रुपए खर्च नहीं कर पाए हैं।

बीते दिनों कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने कांग्रेस सरकार में मिले जतन योजना के खर्च में लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मरम्मत हो चुके भवन का परीक्षण-निरीक्षण करने जिले भर के तकनीकी अफसर व इंजीनियर की टीम को नोडल और जांच अधिकारी बनाया है। टीम जिले के पांच ब्लॉक में जतन योजना में 550 स्कूलों में हुए खर्च का परीक्षण करेगी। लेकिन जिस मरम्मत कार्य को शुरू नहीं किया गया, स्वीकृति राशि का उपयोग साल भर में क्यों नहीं हो सका, उसकी जांच के लिए अब तक कोई कमेटी नही बनाई गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी आनंद सारस्वत कहते हैं कि कार्य प्रगति के आधार पर रुपए जारी हुए। जहां खर्च हुए उसका परीक्षण कराया जा रहा है। जिन भवनों के मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है, उसे दोबारा शुरू कराए जाने की प्रक्रिया आरईएस विभाग करा रही है। जहां मरम्मत की मांग आ रही है, स्टीमेट मंगाकर मरम्मत की मंजूरी विधिवत दी जाएगी।

बुलडोजर कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने भाजपा पार्षद को सड़क पर पटका

बालोद। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने बीजेपी के पार्षद को घर से घसीटे हुए सड़क पर ले जाकर पटक दिया। बालोद जिले के गुरूर नगर में सुबह से ही परिसर को तोड़े जाने के मामले को लेकर शहर पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया था। ऐसे में एक और वीडियो ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। दरअसल, बीजेपी के महिला पार्षद कुंती सिंह शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड की पार्षद है। उसे कुछ परिसर से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं ने घर से खींचते हुए निकाला और सड़क पर ले जाकर पटक दिया, जिसका वीडियो फुटेज सामने आया है।

बता दें कि बीजेपी के महिला पार्षद के प्रति आक्रोशित महिलाओं ने उसे घर से ले जाते देख उसके घर के लोग भी महिला के साथ-साथ बाहर निकले। महिलाओं ने जब उन्हें सड़क पर पटक दिया, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें छुड़ाया। उसे वापस घर लेकर गए। पूरे मामले में थाना प्रभारी गुरुर दिनेश कुर्रे ने बताया कि मामले में पार्षद की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें वीडियो के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है।

दरअसल नगर के बाजार चौक में निर्माण अधीन 45 परिसर को पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से दहा दिया। इसके बाद परिसर से जुड़े लोग काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सभी पार्षदों का दरवाजा खटखटाया और जो पार्षद मिले, जिसमें प्रमुख रूप से कुंती सिंह शामिल रही। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने पार्षद के घर घूसकर खरी-खोंटी सुनाने लगी। इसके बाद उसे पकड़ कर सड़क पर ले जाकर पटक दिया गया। इसके बाद कुछ लोग भाजपा कार्यालय भी पहुंचे थे,लेकिन वहां पर लोग अंदर से ताला लगाकर बैठ गए थे। इस दौरान आक्रोशित लोग हाथों में पत्थर लेकर पहुंचे हुए थे।

हाथियों के हमले से बुजुर्ग दंपत्ति घायल मकान को किया ध्वस्त, गांवों में अलर्ट जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमर्डा परिक्षेत्र में एक बड़े हाथियों के दल ने बगबंध गांव में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने महुआ खाकर मदमस्त होकर ग्रामीण के आवास को ढहा दिया। हाथियों के इस हमले में बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार, गोमर्डा परिक्षेत्र में 25 हाथियों का दल भ्रमण कर रहा है। बीती रात हाथियों के दल ने बगबंध गांव में जमकर उत्पात मचाया। वहीं एक मकान में बोरियों में रखे महुआ खाकर हाथी मदमस्त हुए और ग्रामीण के घर को ढहा दिया। इस घटना की सूचना पर हाथी मित्र दल और रेंजर अजय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जिसके बाद हाथियों को खडेड़ा और घायल बुजुर्ग दंपत्ति चैतराम बारिहा और ननकी दाई को उपचार के लिए बरमकेला अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पीड़ितों को वन विभाग की ओर से 5 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। वन अधिकारियों ने जंगल क्षेत्र से सटे गांवों के लोगों से महुआ घर में नहीं रखने की अपील की है। ताकि वे हाथियों से सुरक्षित रह सकें। बता दें कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पिछले एक वर्ष से 25 जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ग्रामीण को हाथी ने कुचलकर मार डाला, पूरे इलाके में दहशत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शनिवार की सुबह डोरी बीनने गए एक ग्रामीण को हाथी ने कुचलकर मार डाला। जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत की खबर लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में कूड़ेकेला निवासी राजू दास 45 वर्ष शनिवार की सुबह डोरी बीनने जंगल गया हुआ था। ग्रामीण जब डोरी बीनने में व्यस्त था इसी बीच अचानक हाथी से उसका सामना हो गया और फिर हाथी ने उसपर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छाल रेंज में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत की खबर लगते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गांव के ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में एक ही हाथी विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम एवं छाल पुलिस मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

गांजा तस्करी करने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग में क्राइम ब्रांच और कुम्हारी पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने एक मालवाहक से बड़ी मात्र में गांजे के खेप के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मालवाहक से 20 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिसा से दुर्ग की ओर से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। जिसपर क्राइम ब्रांच और कुम्हारी थाना पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मालवाहक में गांजा तस्करी की जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के बताए वाहन को रोक कर चेक किया। जिसमें प्लास्टिक बोरी में 20 किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में एक ओडिसा पुलिस के जवान और एक आरोपी मालवाहक का ड्राइवर बताया जा रहा है।

शादी से एक रात पहले दुल्हन के साथ मारपीट, गहने लूटे

कोरबा। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के तहत शारदा विहार सामुदायिक भवन में दो दिनों पहले सीतामढ़ी निवासी रवि यादव की बहन पूजा यादव की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, दो दिन पहले हल्दी का रस्म हुआ मेहमान और पूरा परिवार कार्यक्रम होने के बाद सब अपने-आप कमरे में सो गए। दुल्हन भी अपने कमरे में आराम कर रही थी पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। इस दौरान अज्ञात चोर मौके पर पहुंचे और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे इस दौरान दुल्हन पूजा यादव की नजर पड़ी और वह चिल्लाने लगी। इस दौरान लुटेरे दुल्हन की पिटाई करते हुए सोने चांदी के जेवरात और 50,000 नगदी रकम लेकर भाग गए। इसकी शिकायत मानिकपुर चौकी पुलिस से की गई जहां पुलिस ने मामले का गंभीरता से लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया जिसकी मदद से एक अपचारी बालक को पकड़ा गया उसके कब्जे से सोने चांदी के गहने बरामद किए गए। वहीं पूछताछ में बातें सामने आई की अन्य साथी उसके फरार हैं जिसकी तलाश की जा रही है।

जहरीला पुटु खाने से एक ही परिवार के चार लोग बीमार

कोरबा। कोरबा में बारिश के दिनों में पुटू का सेवन करना लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानीकारक है बावजूद इसके लोग इसका सेवन करने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही कुछ हरदीबाजार में हुआ जहां जंगली पुटू का सेवन करने से एक ही परिवार के चार लोगों की हालत गम्भीर हो गई। जहां आनन-फानन में सभी को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया,जहां उनका उपचार जारी है। ये मामला हरदीबाजार ईलाके का है,जहां मिरी परिवार के घर में यह घटना सामने आया है बताया जा रहा है,कि शुक्रवार बीती रात पूरा परिवार रात के वक्त सभी एक साथ खाना खाया जहा पुटु सब्जी का सेवन किये उसके बाद सभी अपने कमरे में सोने चले गए। जिसके बाद एक एक कर चारों की सेहत खराब होने लगी। रात करीब तीन बजे आनन-फानन में सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया,जहां उनका उपचार जारी है। तत्काल उपचार मिल जाने से सभी की जान बच गई,नहीं तो कुछ भी हो सकता था।

मलेरिया से पांच साल की बच्ची की हुई मौत

जगदलपुर। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में शुक्रवार की शाम बीजापुर से रेफर आई एक पांच वर्षीय बच्ची की मलेरिया से मौत हो गई। बच्ची की मौत के साथ ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। सभी का रो रोकर बुरा हाल है। मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि बीजापुर निवासी दीक्षिता रेंगा पांच वर्ष को मलेरिया होने के कारण उसके परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर ले गए। बच्ची की खराब हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे मेकाज रेफर कर दिया। मेकाज पहुंचने से पहले ही बच्ची की हालत काफी खराब थी। यहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बरसात आने के साथ ही शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार मलेरिया के मरीज बढ़ रहे है, देखा जाए तो मेकाज में रोजाना दो से तीन मरीज मलेरिया से पीड़ित आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस्तर जिले के अंदुरुनी इलाकों में मलेरिया के काफी संख्या में मरीज मेकाज आ रहे हैं।

पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने खोला मोर्चा

■ ईश्वर ठाकुर पर लगाए गंभीर आरोप, अविश्वास प्रस्ताव लाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों और नगर पालिकाओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में जुटी है। दुर्ग जिले के जामुल पालिका में भी काबिज भाजपा के पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस के 8 पार्षदों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चन्द्राकर के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अहिवारा विधानसभा के जामुल पालिका में वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में भाजपा के जामुल पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर पर कई गम्भीर आरोप लगाए हैं। ईश्वर ठाकुर पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा विगत 10 महीनों से परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई, जिसके कारण जनता के हित से जुड़े विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

वहीं वार्ड तीन संतोषी चौक में अधोसंरचना मद से 17 लाख के कार्य में भगवान राम चन्द्र की मूर्ति स्थापित करने के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। सरोजनी चन्द्राकर ने ज्ञापन में बताया है कि पालिका अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका की शासकीय फाइलों को अनाधिकृत बाहरी व्यक्ति से अवलोकन कराकर ही हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे नगर पालिका के दस्तावेजों की गोपनियता भंग हो रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ पार्षद भी पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर से नाराज चल रहे हैं। पालिका अध्यक्ष पर अपने ही भाजपा पार्षदों के साथ विकास कार्यों को लेकर भेदभाव करने का आरोप है इसलिए फिलहाल भाजपा पार्षदों ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर मौन समर्थन दे दिया है।

दरअसल जामुल नगर पालिका में वर्तमान में भाजपा के 11 व कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। 20 दिसम्बर 2021 को दिसम्बर में हुए निकाय चुनाव में भाजपा 10 और कांग्रेस के 5, निर्दलीय 4 और जोगी कांग्रेस से एक पार्षद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा से वार्ड 10 की पार्षद रामप्यारी वर्मा और वार्ड 18 की पार्षद तिलेश्वरी देवांगन ने अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जॉइन कर लिया था। इसके अलावा जोगी कांग्रेस से पार्षद दुर्गा वैष्णव और निर्दलीय पार्षद अश्वनी साहू , निशा चन्नेवार ने भी कांग्रेस जॉइन कर लिया। इस तरह कांग्रेस पार्षदों की संख्या 10 हो गई। वहीं वार्ड 15 और 16 के निर्दलीय पार्षद के राजू और चुम्मन वर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इन तरह दलबदल के बाद लोकसभा चुनाव से पहले ही वार्ड 14 के कांग्रेस पार्षद रामदुलार साहू (गुल्ली) ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षदों की सख्या 9 हो गई। अब सभी कांग्रेसी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जयसिंह के वर्षों का घर बनाने का सपना हुआ साकार

सुकमा। अपने खुद के घर का सपना सभी देखते हैं। स्वयं का एक पक्का मकान हो, जिसमें वह परिवार के साथ सुख से जीवन यापन करें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में इस दिशा में बेहतर कार्य करते हुए सुकमा जिले में जरुरतमंदों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पहली प्राथमिकता के साथ आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके परिणामस्वरुप पूरे सुकमा जिले में तेजी से पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है। पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को बकाया किश्त जारी होने के बाद अब अधिकांश लोगों का मकान पूर्ण हो गया है।

सुकमा जिले के जनपद पंचायत छिन्दगढ़ के ग्राम पंचायत किन्दरवाड़ा निवासी लाभान्वित हितग्राही श्री जयसिंह उर्फ राजूराम ने बताया कि पहले अपने परिवार में पत्नी श्रीमती श्यामबती नाग और पुत्र अमित नाग के साथ पुराने कच्ची छत और मिट्टी की दीवार वाले झोपड़ी में रहते थे। जिसमें रहने के लिए परिवार के साथ काफी कठिनाई का सामना करना पडता था, कच्ची छत होने के कारण हमेशा बारिश के समय छत से पानी टपकने के कारण हम पूरे परिवार कई रात ठीक से सो भी नहीं पाते थे। उन्होंने बताया कि हमारी आय खेती एवं गांव में ही मजदूरी पर निर्भर है। सीमित आय होने के कारण आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पक्का बना पाये। उन्होंने बताया कि गांव में ही ब्लॉक कोर्डिनेटर सुश्री नेहा मंडावी ने पीएम आवास के बारे में जानकारी दी। हितग्राही श्री जयसिंह ने बताया कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास की स्वीकृति पश्चात् देखते ही देखते पूरी किश्त मिलने से हमारे बरसों का घर बनाने का सपना पूरा हुआ।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर दी गई बिदाई

रायपुर। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद

पनगढिया तथा आयोग के अन्य सदस्यों को नई दिल्ली रवाना होने के पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर बिदाई दी गई। इस अवसर पर वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल, एनआरडीए के सीईओ श्री सौरभ कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगरीय विकास विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार, वित्त कोष लेखा विभाग के संचालक श्री महादेव कावरे सहित अन्य अधिकरी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना 21 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 21 जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट एवं 19 जिलों में 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जशपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के कुछ स्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कोरबा जिले में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वहीं सरगुजा जिले में 75.7 मिमी, बलरामपुर जिले में 70, दंतेवाड़ा में 63.1, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 47.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक औसत से 31 फीसदी बारिश कम हुई है।

बिलासपुर हाई कोर्ट में अवमानना मामलों की पेंडेंसी में आई कमी

रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट में लगातार अवमानना मामलों की पेंडेंसी में कमी आई है। मार्च 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के प्रभार संभालने के बाद से ही अभी तक 1143 मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। वर्तमान में 10 जुलाई की स्थिति में 944 मामले ही लंबित है। खास बात है कि यह पहली बार हुआ है कि अवमाननों मामलों की सुनवाई और निराकरण के लिए चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने पहल करते हुए अलग से रोस्टर जारी किया है। इससे अब अवमानना मामलों की सुनवाई दो से अधिक कोर्ट में हो रही है, जिससे प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण हो रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में हाई कोर्ट में 2299 मामले अवमानना के लंबित थे। इसके बाद मार्च 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने ज्वाइन करने के साथ ही इसके लिए अलग से व्यवस्था की। पिछले करीब एक सालों में 720 और मामले अवमानना के दायर हुए। उसके बाद भी लंबित प्रकरणों की संख्या नहीं बढ़ी और तेजी से निराकरण किया गया।

महतारी वंदन के पैसों का रत्ना कर रहीं म्यूच्युअल फंड में निवेश

रायपुर। जब महतारी वंदन योजना के पैसे रत्ना कन्नौजे के खाते में आये तो उन्होंने इसे अपने बेटे की शिक्षा संबंधी जरूरतों पर निवेश के बारे में सोचा। वे निवेश विशेषज्ञों से मिली। निवेश के जानकारों ने उन्हें बताया कि शेयर बाजार में लंबे समय में पैसा काफी बढ़ता है यदि सोच समझ कर लगाया जाए। चूंकि सभी लोग बाजार के विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए म्यूच्युअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। रत्ना ने पूछा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है तो उन्हें बताया कि शेयर बाजार के जानकार विशेषज्ञ बहुत से शेयरों में जिनके बढने की अच्छी संभावना होती है म्यूच्युअल फंड के माध्यम से पैसा लगाते हैं और इसके बढने पर लाभ यूनिट धारक का होता है। रत्ना ने जो फंड खरीदा, उससे अब तक आये रिटर्न देखे। उन्हें लगा कि अभी बेटे के उच्च शिक्षा में समय है अतएव एसआईपी में निवेश किया जा सकता है फिर एसआईपी शुरू कर दिया। अब महतारी वंदन योजना का पैसा जिस दिन खाते में आता है उसके अगले दिन ही वो एसआईपी की नियत तिथि में पैसे जमा कर देती हैं। रत्ना ने बताया कि बेटे की खुशियों के लिए एक ठोस आधार तैयार हो गया है। हर महीने की सुरक्षित आय से मैं एसआईपी में निवेश करूंगी।

डायरिया से 5 बैगा आदिवासियों की मौत जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी

रायपुर। कवर्धा जिले में डायरिया से बैगा आदिवासियों की मौत मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी गांव का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। जांच कमेटी में विधायक इंद्रशाह मंडावी, जनकध्रुव, पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरी राम, नेता महेश चंद्रवंशी, नीलकंठ चंद्रवंशी शामिल हैं। बता दें कि सोनवाही और बोड़ला में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। डायरिया से 5 बैगाओं की मौत हुई है।

शुभ घड़ी आई, साय कैबिनेट ने अयोध्या धाम में किए श्रीरामलला के दर्शन

उपहार में शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा जल, सीताफल विष्णु भोग का चावल अनारसा तथा करी लड्डू एवं कोसे के वस्त्र भेंट किए

रायपुर। अयोध्या धाम में पवित्र राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में नारा गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह पूरा परिसर राम भक्ति के माहौल में, ननिहाल से आए भक्तों की स्नेह सिक्त वाणी से गुंजायमान हो गया। जिस तरह माता शबरी की शिवरीनारायण में भगवान श्री राम के पुण्य दर्शन की इच्छा पूरी हुई थी। वही साध ननिहाल के हर राम भक्त को होती है। उसी तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी कैबिनेट की भी रामलला के दर्शन की इच्छा आज पूरी हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित उनके कैबिनेट के सदस्यों ने आज अयोध्या धाम पहुंचकर श्रीरामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भाँचा राम के ननिहाल का उपहार भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल, अनारसा,

करी लड्डू तथा कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या धाम आए। भगवान श्रीराम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। भांचा राम के दर्शन के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे। भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोगों को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया तो सोचा कि जब अपने भांजे के दर्शन के लिए जाएंगे तो उनके लिए ननिहाल की तरफ से क्या उपहार लेकर जाएं। फिर विचार आया कि इससे अच्छा उपहार भगवान श्रीराम के लिए क्या हो सकता है कि हम उस पवित्र भूमि शिवरीनारायण से बेर ले जाकर भगवान को भेंट करें, जहां के बेर खुद माता शबरी ने प्रभु श्रीराम को अपने हाथों से खिलाये थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जूठे बेरों का स्मरण हमेशा के लिए लोक स्मृति में दर्ज हो गया है। माता शबरी की इस धरती से भगवान श्रीराम के लिए यह उपहार ले जाने का हमें सौभाग्य मिला इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय प्रदेश है। यहां माता शबरी और अनेक जनजातीय विभूतियों ने भगवान श्रीराम का स्वागत किया है। हमारी यह धरती धन्य है। यह अद्भुत संयोग है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल भी है और यह उनके वन गमन पथ का हिस्सा भी है। रामकथा से जुड़े विद्वान बताते हैं कि श्रीराम ने अपने वनवास के चौदह वर्षों में दस वर्ष यहीं गुजारे। उन्होंने रामायण के प्रसंगों से भी अपनी बात बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों से अपार प्रेम की कहानी कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में अयोध्या पहुंच कर छत्तीसगढ़ के लोगों के अपने आराध्य के प्रति अगाध स्नेह और भक्ति व्यक्त करने का माध्यम बना हूँ। रामलला के दर्शनों से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम ने हमें रामराज्य का आदर्श दिया है। छत्तीसगढ़ में रामराज्य के आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं। श्रीरामलला का दर्शन कर हमने प्रभु से अपने प्रदेश के सुख-समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के बहुत से श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। उन सबसे श्रीरामलला के भव्य मंदिर और उनकी मंजुल मूर्ति की प्रशंसा सुनकर मन बहुत प्रसन्न होता था। आज हमें भी रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही श्री किरण देव, श्री अजय जामवाल एवं श्री पवन साय भी मौजूद रहे।

रायपुर में लारेंश-अमन गैंग के शूटरों ने की दिनदहाड़े फायरिंग

कोयला कारोबारी को टारगेट बनाकर शूटर ने चलाई गोली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी पर दो अज्ञात शूटरों ने गोली चलाई है। पुलिस को आशंका है कि लारेंश बिश्नोई और अमन साहू गैंग के शूटरों ने दो बार फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि एक फायरिंग हवा में और दूसरी फायरिंग कार पर लगी। घटना लगभग सुबह 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इलाके में हडकंप मच गया है। हालांकि गोलीकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है, जिसे कोयला कारोबारी को टारगेट किए थे वे सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। इसके अलावा पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है।

रायपुर एएसपी सिटी लखन पटले ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर के थाना तेलीबांधा अंतर्गत पचपेड़ीनाका से तेलीबांधा के बीच सर्विस रोड में एक कारोबारी के ऑफिस के सामने दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हवाई फायर करते हुए दिखाई दिए। शहर में इस घटना से पहले रायपुर पुलिस ने इसी प्रकार के झारखंड के एक गैंग को रायपुर में घटना को अंजाम देने से पहले पकड़ा था। इस घटना में भी इसी गैंग पर शक है। फिलहाल शहर में नाकेबंदी कर शूटरों की तलाश की जा रही है।

इस घटना से पहले रायपुर पुलिस ने राज्य के दो कारोबारियों की हत्या करने आए लारेंश बिश्नोई और अमन साहू गैंग के चार शूटरों को गिरफ्तार किया था। उस समय शूटर दो कोयला कारोबारी की हत्या करने रायपुर पहुंचे थे, लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले रायपुर पुलिस ने चार शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था।

कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चलाने वाले आरोपियों की बाइक बरामद

राजधानी में दिनदहाड़े थाने के नजदीक कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी की है। वहीं गोली चलाने वाले युवकों की बाइक को तेलबांधा क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है। यह गाड़ी झारखंड की है। आशंका जताई जा रही है कि अमन साहू गैंग ने फायरिंग की है।

यह वारदात आज सुबह करीब 11 बजे की है। गोली चलाने के बाद युवकों के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो युवक गोली चलाने के बाद वही पर घूमते नजर आ रहे।

बाइक सवार दो आरोपी गोली चलाने के बाद फरार हो गए थे, जिसकी छ॥ 01 ष्ठरु4692 पल्सर बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है। शहर के लगभग 10 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं।

'संविधान हत्या दिवस' पर कांग्रेस को आपत्ति

कहा- यह बाबा साहब का अपमान

रायपुर। केंद्र द्वारा संविधान की हत्या दिवस घोषित करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस संचार सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़कर बाबा साहब का अपमान किया है। संविधान को खत्म करने और बदलने की साजिश बीजेपी कर रही है। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं देकर देश की जनता ने संविधान को बचा लिया।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने साय मंत्रिमंडल के अयोध्या दर्शन की तुलना कालनेमी से की है। उन्होंने कहा कि यह कालनेमी के समान भक्ति हैं। भाजपा का प्रोपोगेंडा है। भाजपा सरकार बने 6 माह हो गए, लेकिन अब तक चंदखुरी नहीं गए। भाजपा सरकार ने राम वन गमन परिपथ का काम रोक दिया।

रामविचार नेताम के कांग्रेस में जूतमपैजार के आरोप पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रामविचार नेताम भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री से भी सीनियर हैं, फिर भी उनकी उपेक्षा हो रही है, इससे वे फ्रस्टेट हो गए हैं। उलूल-जुलूल बयानबाजी करना उनकी आदत हो गई है।

वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस सर्वे करवाएगी।

उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में 3000 से अधिक वार्ड हैं। स्थानीय स्तर के नेताओं की भूमिका वहां के चयन में महत्वपूर्ण रहेगी। उनकी अनुशंसा पर ही प्रत्याशी चयनित होंगे। प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निचले स्तर के नेताओं को निर्देशित कर दिया गया है।

छात्र जिस मुकाम पर हों गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा से ही हो पाता है संभव : टीपी शर्मा

लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रवेश उत्सव

रायपुर। शनिवार को लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर का शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम गुरुकुल हॉल में किया गया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टी.पी. शर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भातखंडे ललित कला शिक्षण समिति के अध्यक्ष तरल मोदी ने किया। मुख्य अतिथि टी.पी. शर्मा ने नवप्रवेशित छात्राओं को कॉपी, पेन, पुस्तक एवं मिष्ठान भेट कर स्वागत किया।

उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र किसी भी स्थान पर पहुंचे वह अपने गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ही संभव हो पाता है । समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी ने संछिप्त उद्बोधन से विद्यालय की स्थापना एवं उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए नवप्रवेशित छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की ।

कार्यक्रम के अध्यक्ष तरल मोदी द्वारा छात्राओं को सुभाशीष प्रदान किया गया । इस अवसर पर समिति की सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल, श्रीमती पूजा दानी, आर.के. गुप्ता विशेष रुप से उपस्थित थे। गुरुकुल महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ श्रीमती संध्या गुप्ता, कमलादेवी संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विद्या नाथ सिंह एवं लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य श्रीमती मनीषा गहोई के द्वारा साल,श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया ।कार्यक्रम का संचालन सुश्री एस.एस. सिद्दीकी, उच्च श्रेणी शिक्षिका लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर द्वारा किया गया । धन्यवाद ज्ञापन भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति रायपुर की सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल ने दिया इस अवसर पर विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ शिक्षक,शिक्षिका एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे ।

करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला सी-शोर ग्रुप चिटफंड कंपनी का संचालक गिरफ्तार

रायपुर। करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपित सी-शोर ग्रुप चिटफंड कंपनी के संचालक प्रशांत कुमार दास को भुवनेश्वर से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दास मैजेस्टिक एपार्टमेंट शांति नगर, थाना लक्ष्मी सागर, भुवनेश्वर जिला खुर्दा (ओडिशा) का निवासी है। वह 12 साल से फरार था।

ओडिशा में आरोपित की कंपनी के नाम पर अलग-अलग स्थानों पर स्थित 400 एकड़ भूमि, फैक्ट्री, मकान, वाहनों और सोना-चांदी को क्राइम ब्रांच ओडिशा और ईडी द्वारा जब्त कर जांच की कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। आरोपित के विरुद्ध पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही आरओसी के 400 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपित की संपत्ति लगभग 1,200 करोड़ रुपये की है। वह ओडिशा के मामले में पांच वर्ष जेल काट चुका है। सी-शोर ग्रुप आफ कंपनी के निवेशकों और एजेंटों ने वर्ष 2013 में थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सी-शोर ग्रुप आफ सिक्यूरिटी लिमिटेट, भुनेश्वर व कटक में स्थित है। डॉयरेक्टर प्रशांत कुमार दास, अध्यक्ष एलएलएन सतपथी और ब्रांच मैनेजर दिलीप मोहंती द्वारा थाना सिविल लाइन, रायपुर में 2007 में किराए में मकान लिया गया था। मार्च, 2007 में सिमरन होटल और अन्य स्थानों पर सेमिनार आयोजित कर एजेंटों को जमा राशि में एक वर्ष में 12 प्रतिशत और छह वर्ष में 24 प्रतिशत का लाभांश, आकर्षक कमीशन और विदेश घुमाने का प्रलोभन देकर लगभग 370 निवेशकों से चार करोड़ रुपये निवेश कराया गया। मई 2012 में कंपनी बंद कर आरोपित फरार हो गए थे। प्रशांत कुमार दास पूर्व में अंगूल ओडिशा के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। उसके बाद में एसबीआई लाइफ प्राइवेट एजेंसी में काम किया। इसके बाद आरोपित ओडिशा में सी-शोर ग्रुप के नाम से अलग-अलग प्रकार की एजेंसी जैसे-सी-शोर फार्मेसी, सी-शोरवाटर, सी-शोर डेयरी, सी-शोर राइस मिल एवं अन्य एजेंसियां खोलकर उत्पादों का उत्पादन कर बिक्री करता था। इसके बाद कंपनी को आगे बढ़ाने और अधिक फायदा कमाने के उद्देश्य से प्रिफेंशियल शेयर स्कीम लाया। इसमें ग्राहक को शेयर देकर मालिक बनाया जाता था। कई स्थानों पर सेमिनार आयोजित कर अलग-अलग लोगों को अपने झांसे में लेकर शेयर देकर ग्राहक बनाकर रकम ऐंठता था।इसी तरह उसने रायपुर सिविल लाइन में कार्यालय खोला, जिसमें वह कार्गो कुरियर का काम करता था। रायपुर के अलग-अलग स्थानों पर सेमिनार आयोजित कर लोगों को अपने झांसे में लेकर शेयर देकर मोटी रकम वापस करने सहित अन्य प्रलोभन देकर ग्राहकों से रकम प्राप्त करता था।

मौसमी बीमारियों रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें : उपमुख्यमंत्री

सुदूर वनांचल क्षेत्र चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल के शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन डीएमएफ से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिए

रायपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा कल शुक्रवार को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम सोनवाही पहुंचकर ग्रामीणों सहित पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम सोनवाही में 10 जुलाई को हुई दो ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने ग्राम सोनवाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाए गए अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उपचार कराने आए मरीजों से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री जनमन योजना पर जिस तरह से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उस पर तेजी से कारवाई करते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि वनांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में मौसमी बीमारी, डायरिया, उल्टी दस्त और जलजनित बीमारियों का संक्रमण न हो इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कलेक्टर को वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने और और मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के

निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सुदूर वनांचल क्षेत्र चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल के शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन डीएमएफ से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल सभी गांवों में स्वास्थ्य शिविर, जल स्त्रोतो का क्लोनिशेन कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पूरे घटना की विस्तृत जानकारी भी ली। कलेक्टर श्री महोबे ने बताया कि ग्राम सोनवाही में 10 जुलाई को दो ग्रामीणों की मौत हुई है। पांच ग्रामीणों की मृत्यु होने की बात सामने आई थी। इस विषय पर बोड़ला एसडीएम और सीएमएचओ को जांच और घर-घर पहुंच कर सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे। सोनवाही में जो पांच ग्रामीणों की मौत की खबर थी, वह अलग-अलग कारणों से और अलग-अलग जगह में हुई है। सभी का मृत्यु का कारण डायरिया या उल्टी-दस्त नहीं हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल राज ने बताया कि 10 जलाई को गांव में दो ग्रामीणों की मृत्यु होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला के चिकित्सक और स्वास्थ्य अमला 10 जुलाई को पहुंचकर गांव के आदिवासी बालक आश्रम छात्रावास में अस्थायी रूप से अस्पताल बनाया गया और वहां ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण का काम शुरू किया गया। दूसरे दिन 11 जुलाई को कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तर और चिल्फी के और अतिरिक्त स्वास्थ्य टीम को भेजकर ग्राम सोनवाही में तैनात किया गया। सीएमएचओ डॉ राज ने बताया कि 10 जुलाई को गांव के सोनसिंह पिता ईतवारी उम्र लगभग 45 वर्ष और एक महिला श्रीमती फूलबाई पति मंगल सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष की मृत्यु की सूचना मिली। ग्रामीणों के मुताबिक सोनसिंह अपने खेत से काम कर घर लौटा था, उन्होंने अपने तबियत खराब होने की जानकारी अपने घर वालों को दी। इसके बाद उन्होने उल्टियां शुरू हुई और तीन से चार घंटे के दौरान उनकी घर पर ही हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक इसी प्रकार महिला फूलबाई की मृत्यु भी उल्टी से हुई। दो ग्रामीणों की अकास्मिक मृत्यु के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की गई।

नेपाल की प्रचंड राजनीति में सत्ता परिवर्तन

अशोक के. मेहता

नेपाल में नए गठबंधन का लक्ष्य देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देना और लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार पेश करना है। शुक्रवार को, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. ओली की यू.एम.एल. ने वामपंथी गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया था। इसके साथ ही प्रचंड की सरकार गिर गई और उन्होंने पी.एम. पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस (एन.सी.) और ओली की यू.एम.एल. (सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टियां) के बीच पिछले सोमवार को आधी रात को 7-सूत्रीय समझौता हुआ, जो दिसंबर 2022 के बाद से चौथी सरकार बनाएगा, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सी.पी.एन. माओवादियों की किंग-मेकर भूमिका को समाप्त करेगी। एक एन.सी. नेता ने मुझे बताया कि सौदे से एक दिन पहले भूटानी शरणार्थी घोटाले से जुड़े बेचैन झा की गिरफ्तारी, जिसके निशान एन.सी. और यू.एम.एल. के शीर्ष नेताओं तक पहुंचते हैं, ने इस सौदे को गति दी। गृह मंत्री रबी लामिछाने, जिन्हें एन.सी. ने पोखरा सहकारी धोखाधड़ी मामले में संसद में निशाना बनाया था और यू.एम.एल. ने उनका बचाव किया था, ने इस सौदे को भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए ओली और देउबा की कोशिश कहा। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने गिरिबंधु चाय बागान भ्रष्टाचार मामले के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। 7-सूत्री सौदा अनिवार्य रूप से संसद के शेष 40 महीनों के दौरान सत्ता-सांझाकरण के बारे में है, जिसमें देउबा ने ओली को पहला प्रधानमंत्री देने की पेशकश की है क्योंकि वह 2027 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वे यू.एम.एल. के साथ सांझा किए जाने वाले मंत्रालयों की संख्या पर सहमत हो गए हैं, जबकि एन.सी. को वित्त और गृह मंत्रालय दिया जाएगा। एन.सी. और यू.एम.एल. अलग-अलग विचारधाराओं वाले कट्टर दुश्मन हैं। उनके दोनों नेताओं को व्यापक अनुभव है और वे जेल में भी रहे हैं। देउबा 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि ओली 2 बार नेपाल का नेतृत्व कर चुके हैं। देउबा को भारत का चहेता माना जाता है और पश्चिम उन्हें पसंद करता है, जबकि ओली चीन के पसंदीदा हैं, हालांकि वे कट्टर कम्युनिस्ट नहीं हैं, बल्कि दिल से लोकतांत्रिक हैं। 2008 में अंतरिम संविधान के तहत पहले बहुदलीय चुनावों के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 2015 के संघीय, लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान के बाद भी 16 वर्षों में 16 प्रधानमंत्रियों ने कुर्सी का खेल खेला है। चुनावी प्रणाली एक त्रिशंकु संसद बनाती है। इस बीमारी को दूर करना राष्ट्रीय सर्वसम्मति सरकार का उद्देश्य है, जिसके लिए 275 सदस्यों वाले सदन में 184 सीटों के 2 तिहाई बहुमत से संविधान में बदलाव करना है। 10 साल तक चले जनयुद्ध का नेतृत्व करने वाले और परिवर्तनकारी संवैधानिक सुधारों को पेश करने में मदद करने वाले प्रचंड कोई नौसिखिए नहीं हैं। उन्हें सत्ता से प्यार है। अपनी पार्टी के घटते चुनावी आधार के बावजूद, वे सुर्खियों में बने रहने में कामयाब रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चूंकि सरकार गठन संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत था, इसलिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडयाल अनुच्छेद 76 (3) का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी पार्टी के नेता देउबा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिससे ओली को प्रधानमंत्री पद से वंचित होना पड़ेगा। प्रचंड और एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल, जो पहले यू.एम.एल. में थे, दोनों ओली से नफरत करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि वह फिर से प्रधानमंत्री न बनें। वरिष्ठ एन.सी. नेता शशांक कोईराला ने कहा है कि एन.सी.-यू.एम.एल. गठबंधन विपक्षी ताकतों को कमजोर करेगा। एक अन्य एन.सी. शीर्ष नेता शेखर कोईराला ने कहा कि सरकार गठन कानूनी तौर पर 76 (3) की ओर जा सकता है न कि 76 (2) की ओर।

रूस-ऑस्ट्रिया की यात्राओं से नई उड़ान

ललित गर्ग

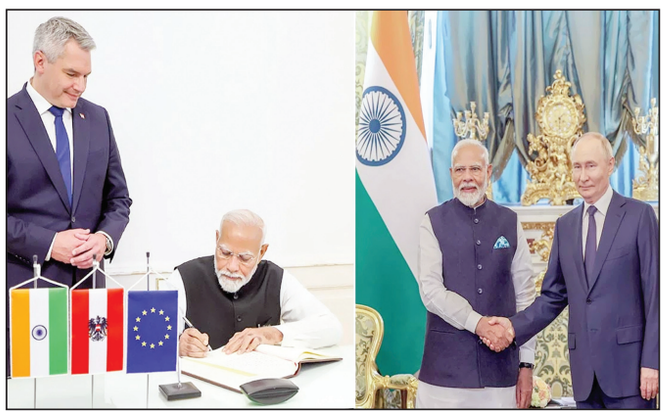

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ-साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। इन दोनों देशों की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली होगी। दोनों देशों की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। सैन्य उत्पाद, व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन दोनों देशों में जो सम्मानभावना देखने को मिली, उससे यही कहा जा सकता है कि मोदी विश्व-नेता के रूप में स्वतंत्र पहचान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत के लिये शुभ है।

निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में अपनी चमक के साथ आगे बढ़ते भारत के लिये रूस की यात्रा कई मायनों में बहुत उपयोगी एवं दूरगामी रही। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में हुए नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात थी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुतिन ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत-रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। भारत-रूस की दोस्ती की गर्माहट से चीन एवं पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है।

यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दुनिया की नजरे लगी रही। एक ध्रुवरीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमरीका और बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की स्थिति एवं उसकी बढ़ती ताकत का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमरीका की सधी प्रतिक्रिया सामने आयी कि इससे उसके भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही इससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो ध्रुवरीय नहीं रही। अमेरीका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। वास्तव में इस आवश्यकता ने भी अमेरीका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि अब भारत का समय आ गया है। वास्तव में आज अमेरीका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। कहना न होगा कि वैश्विक मंच पर योग का विषय हो, या अहिंसा का या फिर आतंकवाद से निपटने का, जलवायु परिवर्तन का मसला हो या फिर जी-20 देशों की अध्यक्षता की बात, भारत, दुनिया को नई दिशा दे रहा है, नई उम्मीदें जगा रहा है।

एक नई ताकत एवं सशक्त अर्थ-व्यवस्था के साथ एक नया ध्रुव बनकर उभर रहा भारत समूची दुनिया की नजरों का ताज बना हुआ है। भारत अब बिना किसी दबाव के किसी भी अन्य ताकतवर देश की नाराजगी मोल लेने का हौसला रखता है। शीतयुद्ध के दौर में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बाद एक धुवीय व्यवस्था का अनुभव दुनिया को मिल चुका है। अब बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में ही संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बन भारत वैश्विक भूमिका को खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है। वैसे भी भारत एक बड़े देश के पाले में कभी नहीं रहा। अनेक संकटों से घिरा होकर भी भारत अपनी बात बुलन्दी के साथ दुनिया के सामने रखता रहा है, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के तीनों कार्यकाल में भारत ने अपने शक्तिशाली होने का भान कराया है।

भारत की रूस से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है। इजरायल से नई दोस्ती के बावजूद फिलिस्तीन पर हमारी रणनीति नहीं बदली है। उसी तरह रूस से अच्छे संबंध का यह मतलब नहीं कि यूक्रेन के मामले में उसे क्लीन चिट दे दें। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। भारत की इस भूमिका के बीच अब अमरीका भी यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल शांति के पक्षधर अन्य देश भारत के साथ मिलकर रास्ता खोजने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौता वार्ता का मंच बनने की इच्छा जाहिर करना यही बताता है।

भारत अहिंसा एवं शांति का हिमायती का देश है और मानता है कि युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध केवल बर्बादी और तबाही लेकर ही आता है। रूस व यूक्रेन के बीच जो सीमा विवाद है वह इन देशों के बीच का मामला है और भारत शुरू से ही कहता रहा है कि इस समस्या का हल केवल बातचीत से ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान भी भारत का यही रुख सामने रखा और स्पष्ट किया कि किसी भी झगड़े को निपटाने का रास्ता केवल वार्तालाप ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने रूस से आस्ट्रिया पहुंच कर भी इस रुख को और खोला और कहा कि भोले-भाले लोगों की हत्या कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध के सन्दर्भ में इस तथ्य को अमेरिका को ही सबसे पहले समझना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से क्या चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा? क्योंकि रूस एवं चीन के बीच बढ़ती मित्रता एवं प्रगाढ़ता समूची दुनिया के लिये एक चिन्ता का सबब है। भले ही अमरीका की ताकत को देखते हुए रूस ने चीन से निकटता बनाई हो, लेकिन भारत से उसकी दोस्ती इन सबसे ऊपर है। फिर भी चीन एवं पाकिस्तान भारत के दुश्मन ही रहे हैं। इन हालातों के बीच मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के भाग्य के लिए नये सूर्य का उदय कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी महत्वपूर्ण यात्रा रूस की रही, उतनी ही महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया की यात्रा भी रही। मोदी ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी निशाने पर लेते हुए पुतिन से कहा कि चीन जहां पाकिस्तान के आतंकवाद को सहयोग-समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अब मोदी की इन बातों का पुतिन पर क्या असर होगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

जहां तक रूस से मित्रता का सवाल है तो यह भारत का परखा हुआ सच्चा मित्र है और भारत यह दोस्ती कभी नहीं छोड़ सकता। पिछले दो दशकों में हमारे सम्बन्ध अमेरिका से भी मधुर हुए हैं परन्तु हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतन्त्र है और दुनिया का कोई भी देश इसे प्रभावित नहीं कर सकता। भारत के द्विपक्षीय सम्बन्ध किस देश के साथ कैसे हैं यह केवल भारत ही तय करेगा। अमेरिका हमें रूस-यूक्रेन के बारे में क्या समझायेगा? भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक महाबड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और भारत शांति एवं अयुद्ध का हिमायती है। हम तो पहले ही यह कह चुके हैं कि भारत बुद्ध-महावीर-गांधी का देश है और इसकी विदेश नीति भी इनसे प्रेरणा लेकर ही तय होती रही है। बदलते वैश्विक सन्दर्भों के बावजूद भारत आपसी शान्ति, अहिंसा, युद्धमुक्त विश्व-संरचना व सह अस्तित्व पर ही विश्वास रखता है। दुनिया की महाशक्तियों द्वारा भारत को तवज्जो देने के पीछे जिन वजहों को देखा जा रहा है, उनमें व्यापारिक प्रगति के साथ शांति एवं अमन-चैन की दुनिया बनाना भी मुख्य है। निश्चित ही मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के लिये 'सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना' एवं 'परिवर्तनकारी क्षण' साबित होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उप-पुराण (भाग-2)

गतांक से आगे...

अल्बेरूनी के वृतान्त में आदित्य और नन्दा- जो नन्दिकेश्वर का अपभ्रंश प्रतीत होता है- नामक औप-पुराणों का भी उल्लेख मिलता है अत: निविवाद ये ग्रन्थ भी नवीन नहीं है, जैसा कि कुतर्की लोग कहते हैं। औपपुराणों के नाम इस प्रकार हैं- (1) सनत्कुमार पुराण (2) बृहन्नारदीयपुराण (3) आदित्य- पुराण (4) मानव प्राण (5) नन्दिकेश्वर पुराण (6) कौर्म पुराण (7) भागवत पुराण (8) वशिष्ठ पुराण (9) भार्गव पुराण (10) मुद्गल पुराण (11) कल्कि पुराण (12) देवी पुराण (13) महाभागवत पुराण (14) बृहद्धर्म पुराण (15) परानन्द पुराण (16) पशुपति पुराण (17) वह्नि पुराण और (18) हरिवंश पुराण, ये सब अठारह औपपुराण हैं।

ये सब मिलकर 54 ग्रन्थ पुराण नाम से विख्यात हैं। इस समय लगभग 43 ग्रन्थ यत्र यत्र छप चुके हैं जो सर्वसाधारण को सुलभता से मिल सकते हैं। कई एक ग्रन्थों का सेठ चान्दमल हैदराबाद [दक्षिण] की लाइब्रेरी में - नाथद्वारे के गोस्वामियों के पुस्तकालय में, एवं काश्मीर और नैपाल के राजकीय पुस्तक भण्डार में पता लगा है। कई एक पुस्तक अभी तक हमारे देखने सुनने में भी नहीं आई शायद कहीं दबी पड़ी हों। अथवा वैदिक साहित्य के अन्यान्य अमूल्य ग्रन्थ रत्नों की भांति यवन बादशाहों के हमामों की धधकती आग में सदा के लिये स्वाहा हो गये हों! इस भेद को ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है।

यद्यपि हमने प्रसंगवशात् यहाँ पुराण के साथ 2 उप-पुराण और औपपुराणों का भी उल्लेख किया है और आवश्यकतानुसार आगे भी किया जा सकता है, तथापि हमारी विवेचना की सीमा सर्वविदित और सर्व सुलभ अष्टादश पुराण ग्रन्थों तक ही परिसीमित है, अत: मुख्यत: इन पर ही विचार किया जाता है।

क्रमश: ...

गोपाल गणेश आगरकर

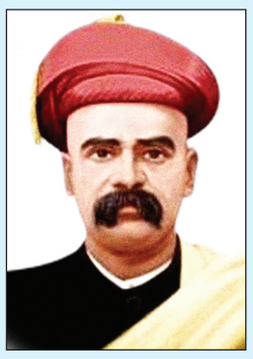

गोपाल गणेश आगरकर का नाम भारत के प्रसिद्ध समाज सेवकों में लिया जाता है। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहपाठी रहे थे। उन्होंने सुधारक नामक एक साप्ताहिक भी निकाला था। गोपाल गणेश आगरकर जी वर्ष 1892 में फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे के प्रधानाध्यापक बनाये गए थे और फिर इस पद पर वे अंत तक रहे।

लोकमान्य बालगंगाधर के सहपाठी और सहयोगी गोपाल गणेश आगरकर जी का जन्म 14 जुलाई, 1956 ई. को महाराष्ट्र में सतारा ज़िले के तेम्मू नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने पुणे के दक्कन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने देश और समाज सेवा का व्रत ले लिया था।

आगरकर जी, लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगी यह मानते थे कि शिक्षा-प्रसार से ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जनवरी, 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। परंतु अपने विचारों के प्रचार के लिये गोपाल गणेश आगरकर जी के पास इतना पर्याप्त नहीं था। 2 जनवरी, 1881 से उन्होंने अंग्रेज़ी साप्ताहिक मराठा का और 4 जनवरी से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन आरंभ किया।

वर्ष 1894 में दक्कन एजुकेशनल सोसाईटी की स्थापना हुई और दूसरे वर्ष फर्ग्युसन कॉलेज अस्तित्व में आया। गोपाल गणेश आगरकर तथा लोकमान्य बालगंगाधर तिलक आदि इस कॉलेज के प्रोफेसर थे।

साप्ताहिक पत्र केसरी के सम्पादन में भी गोपाल गणेश आगरकर, लोकमान्य तिलक के निकट सहयोगी थे, परंतु बाल विवाह और विवाह की उम्र बढ़ाने के प्रश्न पर आगरकर जी का तिलक से मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण 1887 में वे साप्ताहिक पत्र केसरी से अलग हो गये। अब उन्होंने स्वयं का सुधारक नामक नया साप्ताहिक निकालना आरंभ किया। 1890 में लोकमान्य तिलक ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी छोड़ दी।

गोपाल गणेश आगरकर 1892 में फ़र्ग्युसन कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किये गए और वे जीवन पर्यंत इसी पद पर रहे। आगरकर जी बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। वे विधवा विवाह के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि लड़कों की विवाह की उम्र 20-22 वर्ष और लड़कियों की 15-16 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया राष्ट्र की उन्नति के लिये सांप्रदायिक एकता को आवश्यक मानने वाले गोपाल गणेश आगरकर जी ने विदेशी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रबल विरोध किया। आर्थिक उन्नति के लिये वे देश का औद्योगीकरण आवश्यक मानते थे।

समाज सुधार के कार्यों में विशेष योगदान देने वाले गोपाल गणेश आगरकर जी का निधन 17 जून, 1895 ई. में 43 वर्ष की अल्प आयु में हुआ।

नेता प्रतिपक्ष बोलते बहुत हैं लेकिन चिंतन नहीं करते

मोहन लाल

यह तो सच है कि विपक्ष में बोलते सिर्फ राहुल गांधी हैं। सिंह गर्जना संसद के बाहर ममता बनर्जी भी करती हैं। हाल के संसद सत्र में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी सुना अन्यथा विपक्ष सदन में कहां दिखाई दिया?

मैं भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों की विवशता समझ सकता हूं कि वह नरेंद्र मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते? प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सिवाय सदन में कहां खड़ा है? लोगों को पता ही नहीं चला। टैलीविजन या प्रिंट मीडिया में कांग्रेस के राहुल गांधी ही दिखाई दिए हैं। यह राहुल गांधी का दुर्भाग्य है कि सदन के बाकी सदस्य उन्हें हंसी में ले लेते हैं। सदन में अमित शाह, मोदी जी, ओम बिरला या राजनाथ ने तेवर तो जरूर दिखाए परन्तु नेता प्रतिपक्ष बोलते ही चले गए। लगता है कि आगामी संसद सत्रों में भी उनके बोलने का क्रम इसी प्रकार का रहेगा। मैंने प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवानी, मधुलिमये और राम मनोहर लोहिया को सुना है। उनके तथ्यों और डैरावाइज के वार्तालाप सत्तापक्ष को परेशान कर देते थे। सदन में नेता प्रतिपक्ष को 'कैबिनेट मंत्री' पद की हर सुविधा उपलब्ध रहती है।

केंद्र में चीफ सैक्रेटरी और विभागों के सैक्रेटरी को उन्हें सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करने के तथ्य उपलब्ध करवाने ही पड़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष के आई.ए.एस. रैंक का एक सचिव भी सत्ता पक्ष उपलब्ध करवाता है। राहुल गांधी संसद के पहले सत्र में ही एक्सपोज हो गए। वह अपनी बचकाना छवि से प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। लगता है कि राहुल गांधी लाड़-प्यार के झूले से अभी बाहर ही नहीं निकले।

हिंदू, हिंदुइज्म या हिंदुत्व की एक नई आलोचना में फंस गए। लगता यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष ने 'हिंदू' शब्द के उदार, व्यापक और सर्वमान्य रूप का चिंतन ही नहीं किया और हिंदू देवी-देवताओं के चित्र सदन में दिखा-दिखा कर यही कहा कि हिंदू 'नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत' ही फैलाता है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष ने हिंदू आस्था के प्रतीक 'राम' को भी इसी नफरत के मुहावरे से जोड़ दिया। परिणाम पत्थरबाजी, धरने, जलूस और अग्नि लगाने तक पहुंच गया। मैं हिंदू समाज से विनती करता हूं कि इटली की संस्कृति में पले-बढ़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को माफ कर दें क्योंकि उन्होंने हिंदू शब्द की व्यापकता और विशालता के बारे पढ़ा ही नहीं। सुना है उन्होंने यूरोप के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं।

डिग्रियां हासिल कर लेने से कोई विद्वान थोड़े ही बन जाता है? मैंने स्वयं में न जाने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं परन्तु हूं तो अज्ञानी, मूर्ख ही न? सदन में उनके दिए भाषण से लगता है कि उन्होंने जीवन में अभावों का सामना नहीं किया। मौत के साए में पढ़ने-लिखने, बोलने और बड़े होने वाले बच्चों का स्वभाव भी दूसरों से नफरत करने वाला हो जाता है। शायद प्रसुप्त मन में राहुल गांधी को यही विचार घर कर गया हो कि सिर्फ मैं और मेरा ही धर्म सच्चा है। बाकी सब धर्म, सम्प्रदाय और पथ नफरत की दुकान चलाते हैं और राहुल गांधी ही सिर्फ ऐसे नेता हैं जो प्यार बांटते हैं? राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। कल उन्हें सत्ता में आना है। उनकी एक 'शैडो' कैबिनेट है अत: अध्ययन चिंतन, मनन तो उन्हें करना ही होगा, और न सही 'हिंदू शब्द' की पवित्रता और व्यापकता का आकलन तो करना चाहिए। मैं, जितनी मेरी बुद्धि है 'हिंदू शब्द' का मूल रूप हिंद समाचार ग्रुप के माध्यम से लोगों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

'हिंदू शब्द' पर विद्वानों ने ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए हैं परन्तु फिर भी 'हिंदू शब्द' का वास्तविक स्वरूप लोगों की समझ से परे है। 'हिंदू शब्द' पर ही मेरी अपनी लाइब्रेरी में 5-7 पुस्तकें तो होंगी ही परन्तु मुझे शक है कि मैं 'हिंदू शब्द' को लोगों को समझा सकूं। हां, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मनीषी लोग अवश्य हिंदू शब्द की व्यापकता समझा सकते हों? हिंदू न कोई धर्म है न कोई सम्प्रदाय या पंथ है। यह तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों की एक 'जीवन पद्धति' है। जीने का एक ढंग है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदू को एक जीवन पद्धति कहा है। हिंदू वह है जो सबको अपना समझता है। सारा विश्व हिंदू का है।

हिंदू का कोई सम्प्रदाय या कोई एक 'देवदूत' या 'पैगम्बर' नहीं। हिंदुओं में किसी एक देवता की पूजा नहीं होती। हिंदू किसी एक दार्शनिक विचार पद्धति में विश्वास नहीं रखता। हिंदुओं में किसी एक सम्प्रदाय का अनुष्ठान नहीं होता। हिंदू एक अमर शब्द है। प्राचीन जातियां, असभ्य और अर्द्धसत्य लोग, सभ्य द्रविड़ और वैदिक आर्य हिंदू थे क्योंकि वे एक मातृभूमि की संतान थे। देवी-देवताओं की पूजा करने वाले अलग-अलग पूजा पद्धतियों का पालन करने वाले सारे हिंदू हैं। हिंदू ने कभी भी किसी विचार, सिद्धांत या चिंतन को असत्य नहीं कहा है। हिंदू सबका मंगल और कल्याण मांगता है। महात्मा बुद्ध ने 'बौद्धमत', महावीर स्वामी ने 'जैनपंथ', बासव ने लिंगायत सम्प्रदाय, संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने 'बारबारी पंथ', श्री गुरु नानक देव ने 'सिख पंथ', स्वामी दयानंद ने 'आर्य समाज', चैतन्य महाप्रभु ने 'भक्ति सम्प्रदाय', कबीर जी ने 'कबीर पंथ', संत रविदास ने अलग पंत की नींव रखी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी ने 'हिंदू शब्द' में एक आकर्षण भरा।

यदि इन सभी सम्प्रदायों या पंथों का चिंतन करें तो कुछ अंतर दिखाई देगा परन्तु यदि गहराई में जाएं तो इन सब में एक उच्चकोटि की एकता दिखाई देगी। हिंदू सिद्धांत सहिष्णु है और सबकी इच्छानुसार, स्वभावानुसार, रुचि अनुसार कोई भी पंथ तथा पूजा-पद्धति अपनाने से रोकता नहीं। हिंदू 'जीवन पद्धति' ही ऐसे है कि जिओ और जीने दो। अत: हिंदू गुस्सा थूक दें और नेता प्रतिपक्ष से कहें कि वह सत्य कहें और तथ्यों पर सदन की मर्यादा बनाए रखें। सबका भला करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान।

आज का इतिहास

1940 द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के बमवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी किया।
1945 इटली ने अगले दिन जापान पर युद्ध की घोषणा की।
1950 कोरियाई युद्ध के एक शुरुआती युद्ध में, उत्तर कोरिया के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के ताएजन में अमेरिकी 24 वें इन्फैंट्री डिवीजन के मुख्यालय पर हमला करना शुरू कर दिया।
1957 राव्या अतीया ने मिस्र की नेशनल असेंबली में अरब दुनिया की पहली महिला सांसद को उकसाने के लिए अपनी सीट ली।
1958 इराक़ में जनरल अब्दुल करीम के विद्रोह के बाद राजशाही व्यवस्था का अंत और प्रजातंत्र की स्थापना हुई।
1960 ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला के माध्यम से आग भड़क गई है। इसमें 225 की मौत हो गई थी। शरण के 225 लोगों की मौत हो गई थी। 300 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
1960 इंग्लिश प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडाल गोम्बे स्ट्रीम चिंपांजी रिजर्व, तांगानिका में जंगली चिम्पांजी के थिसोसियल और पारिवारिक इंटरैक्शन के बारे में अपने अध्ययन की शुरुआत करने पहुंचे।
1965 मंगल के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोज अप तस्वीरें खींची।
1965 नासा के अंतरिक्ष यान मैरिनर 4 ने पिछले मंगल ग्रह से उड़ान भरी थी, जो किसी अन्य ग्रह की सबसे करीब की तस्वीरों को इकट्ठा कर रहा था।
1972 तत्कालीन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
1972 प्लेट अंप और कैचर एक खेल में भाई बन गए हैं। बिल हॉलर अंपायर हैं और टॉम हॉलर टाइगर्स कैचर हैं। कैनसस सिटी रॉयल्स ने 1-0 से जीत दर्ज की।
1973 102 वां ब्रिटिश गोल्फ ओपन खत्म हो गया है। टॉम वेइस्कॉफ ने रॉयल ट्रॉन में 276 रन बनाए। यह उनके लिए एक शानदार सफलता थी।
1978 एलन गिंसबर्ग ने प्लूटोनियन ऑड पूरा किया। यह फिशाइल सामग्री के ट्रेन लोड को रोकता है जो कोलोराडो में स्थित रॉकवेल के परमाणु बम ट्रिगर कारखाने के लिए नेतृत्व किया गया था।
1987 मॉन्ट्रियल में दो-ढाई घंटे के बारिश में 100 मिमी (3.9 इंच) से अधिक बारिश हुई, जिससे गंभीर बाढ़ आई और 220 मिलियन डॉलर से अधिक की क्षति हुई।
1995 एमपी 3 डिजिटल ऑडियो एन्कोडिंग प्रारूप का नाम दिया गया था।

40 साल बाद 'पलटा' गया एक महत्वपूर्ण फैसला

संजय सक्सेना

जब हुकूमत बदलती है तो संवैधानिक संस्थाओं का कामकाज का तरीका और नजरिया भी बदल जाता है। याद कीजिए मोदी सरकार के आने से पूर्व तक कैसे अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान, वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लटकाया जाता रहा था। कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने पर खून-खराबे की बात कही जाती थी। एक बार में तीन तलाक को शरिया की आड़ में सही ठहरा के लाखों मुस्लिम महिलाओं को एक झटके में घर से बेखर कर दिया जाता था और सरकारें तुष्टिकरण की सियासत और मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में उफ तक नहीं करती थीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया की चादर ओढ़कर सरकार पर दबाव बनाने का काम करता था। हलाला के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण को एक परम्परा बना दिया गया था। मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक सम्पति में उनके हुकूक से महरूम रखा जाता था। बहु विवाह महिलाओं के लिये एक अभिशाप बन हुआ है। धर्म की आड़ में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं किसी की भी जमीन मकान पर अपना मालिकाना हक जता देते थे। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक तलाकशुदा बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके शौहर से चंद रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया तो राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलटने में देरी नहीं लगाई थी।

खैर, चालीस साल बाद अब एक बार फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास को दोहराते हुए एक अहम फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ता लेने के हक की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। दोनों जजों ने फैसला तो अलग-अलग सुनाया, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने के लिए पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस कर सकती हैं।सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक वैसा ही है, जैसा कि 23 अप्रैल 1985 में शाहबानो मामले में दिया गया था।

दरअसल, 1985 में इंदौर की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो ने गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति मोहम्मद अहमद खान को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इस फैसले को शरिया में दखलंदाजी करार देते हुए विरोध शुरू कर दिया। उस समय की मौजूदा राजीव गांधी सरकार जो मुस्लिम वोटों की बड़ी दावेदार थी, उसे जब लगा कि उसका मुस्लिम वोट बैंक इस फैसले से खिसक सकता है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कट्टरपंथियों के विरोध के आगे झुक गये और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 लाकर मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

राजीव गांधी सरकार द्वारा लाए गए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 की संवैधानिक वैधता

को 2001 में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। डेनियल लतीफी वकील थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो का प्रतिनिधित्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1986 के कानून की व्याख्या इस तरह से की जिससे की अधिनियम में लागू की गई रोक एक तरह से अप्रभावी हो गई। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के अधिकार इद्दत की अवधि के आगे भी रहते हैं। कोर्ट के इस फैसले ने सुनिश्चित किया कि मुस्लिम महिलाओं को गरिमा के साथ अपना जीवन जीने के लिए उचित मदद मिले।

राजीव गांधी सरकार ने भले ही शाहबानों केस में मुआवजे के सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाले फैसले को कानून बनाकर पलट दिया था,लेकिन मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई कभी थमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में जोर देकर कहा था कि धर्म का पालन करने के अधिकार में दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार शामिल नहीं है। यह बात खास कर लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात की पुष्टि की गई थी कि पर्सनल ला संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। इसी प्रकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शमीम बानो नाम असरफ खान मामले में कहा था कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष इसके लिए आवेदन कर सकती है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया था कि मुस्लिम पति की जिम्मेदारी हैं कि वह तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए गुजारा भत्ता सहित उचित व्यवस्था करें और यह बात इद्दत की अवधि से आगे के लिए भी लागू होती है। इस कड़ी में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को भी नहीं भुलाया जा सकता है।जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक और अवैध करार दे दिया था। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

कुल मिलाकर 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का अपने अहम फैसले में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश व्यापक प्रभाव वाला है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से भरण-पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हों इसमें कोई बुराई भी नहीं हैं। ऐसे फैसलों पर धर्म के नाम पर कतई विवाद नहीं होना चाहिए।लम्बे समय से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हक से महरूम थीं।संभवता अब उन्हें न्याय मिल पाये। क्योंकि इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार की ओर से उठाए गए एक गलत कदम का प्रतिकार करने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है। एक तरह से इस निर्णय के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि 1985 उसकी पूर्ववर्ती बेंच के द्वारा शाहबानो मामले में दिया गया फैसला सर्वथा उचित एवं संविधान सम्मत था भले ही राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट दिया था। 1986 में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर उनके मन मुताबिक और शरिया के अनुकूल मुस्लिम महिला अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करना था।

चालीस सालों में हालात काफी बदल चुके हैं। तब कांग्रेस पावरफुल हुआ करती थी उसकी जगह बीजेपी ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम किसी पंथनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल यही आकर नहीं रुका, इसके आगे भी कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग समुदाय की महिलाओं को भिन्न-भिन्न कानूनों से संचालित नहीं किया जा सकता, बल्कि इस फैसले के साथ कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता भी जताई है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी संदेश दिया है कि देश के लोग संविधान से चलेंगे, न कि अपने पर्सनल कानूनों से, वे चाहे जिस पंथ-मजहब के हों। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश में अलग-अलग समुदायों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के नियम-कानून इस आधार पर हों कि उनका उनका पंथ-मजहब क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, इस फैसले को राजनीतिक दल किस तरह से लेते हैं,यह देखने वाली बात होगी। हां इतना तय है कि बीजेपी इसके पक्ष में खड़ी नजर आयेगी। वहीं विपक्ष से यह अपेक्षा अनुचित नहीं कि उनके नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की प्रशंसा करने के लिए आगे आयेगें, जो पिछले कुछ समय से संसद के भीतर-बाहर संविधान की प्रतियां लहराकर यह दावा करने में लगे हुए थे कि उन्होंने संविधान की रक्षा की है और वे उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सच्ची है तो उन्हें इस फैसले का स्वागत करना ही होगा। वर्ना संविधान बचाने का उसका दावा सियासी ही समझा जायेगा। उधर, इसकी भी पूरी आशंका है कि इस फैसले से कुछ मुस्लिम संगठन असहमति जताने के साथ उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दें।दो सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और बड़ी बैंच बनाये जाने की भी मांग उठ सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को मोदी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं होगी। हो सकता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की भी बात कही है उसी को आधार बना कर मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाये। ऐसा इसलिये भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इस समय मोदी सरकार पर समान नागरिक संहिता,जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिये दबाव बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चार दशक के बाद जिस तरह से अपने 1985 के आदेश को जीवंत किया है, उसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब शाहबानों को गुजारा भत्ता नहीं दिये जाने की बात चलेगी तो राजीव गांधी सरकार का भी नाम आयेगा,जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लम्बे समय तक गुजारा भत्ता देने से महरूम रखा था।

रूस के साथ प्रगाढ़ संबंधों पर फिर लगी मुहर

शोभना जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना जाना एक

तरफ जहां द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाना रहा, वहीं दो ध्रुवों में बंटी दुनिया में भारत ने तटस्थ रह कर संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है। इसके अलावा चीन फैक्टर जैसे जटिल मुद्दे को साधने की कोशिश भी इसका एक अहम पहलू है। हालांकि प्रधानमंत्री ने वहां साफ तौर पर भारत के पुराने स्टैंड को दोहराते हुए कहा कि युद्ध भारत को कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत का यही स्टैंड रहा है कि बातचीत के जरिये समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए और युद्ध बंद किया जाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई है। हालांकि अमेरिका रक्षा विभाग ने कहा कि इन चिंताओं के बावजूद भारत अमेरिका का रणनीतिक साझीदार बना रहेगा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि 'भारत और रूस के लंबे और घनिष्ठ संबंध भारत को यह क्षमता देते हैं कि वह रूस से बिना वजह छेड़े गए इस क्रूर युद्ध को खत्म करने का आग्रह कर सके।' रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को 'ऐतिहासिक और गेम चेंजर' बताया है। एक तर्क यह भी है कि रूस ने मोदी की यात्रा के जरिये दुनिया को यह संकेत दिया है कि वह इस युद्ध की वजह से अलग-थलग नहीं पड़ा है। बहरहाल, भारत ने मोदी की इस यात्रा को सफल बताया है। रूस यात्रा पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है, ''रूस के राष्ट्रपति पुतिन से काफी सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें आपसी व्यापार, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भारत-रूस सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई।'' रूस ने भी कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंध और बढ़ाए जाने पर जोर दिया। साथ ही अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के जरिये द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली जारी रखने का भी फैसला किया। गौरतलब है कि भारत और रूस के बीच सालाना करीब 65 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का निर्यात करीब 5 बिलियन डॉलर है, जो बताता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कितना बड़ा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है और अगर दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की बात करें तो विदेशी मामले के एक विशेषज्ञ के अनुसार यह भारत की तरफ से पश्चिमी देशों को एक संकेत है कि वह अपनी रक्षा और अन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं कर सकता और अपने पुराने साथी और सामरिक सहयोगी रूस को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। भारत में रूस रक्षा उपकरणों के उत्पादन को लेकर सहमत हुआ है। मोदी और पुतिन की मुलाकात इस मायने में भी खास है कि भारत अपने हथियारों की बड़ी जरूरत के लिए भले ही अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है, लेकिन वह इस मामले में रूस से दूर नहीं जाना चाहता है। यात्रा से जुड़े अहम चीन फैक्टर की बात करें तो यह यात्रा रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता से भी जुड़ी हुई है। भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ संबंधों से रूस व चीन के बीच मेलमिलाप को कम किया जा सकता है।

अधर में अटकते जा रहे अजित पवार

अमिताभ श्रीवास्तव

राजनीति की पारिवारिक पृष्ठभूमि और निजी महत्वाकांक्षा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के टूटे गुट के नेता अजित पवार को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होने का अवसर नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा राज्य सरकार में शामिल होने से लेकर लोकसभा चुनाव तक चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में पांच स्थानों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला, जिसमें से एक सीट पर जीत मिली और बारामती जैसी प्रतिष्ठित सीट पर हार मिली। आखिरकार पराजित उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजना पड़ा।

मगर राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे पार्टी के दूसरे नेता प्रफुल्ल पटेल को उस समय झटका लगा, जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपेक्षा अनुरूप स्थान नहीं दिया गया। अब 38 विधायकों के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है और अस्सी से नब्बे सीटों पर चुनाव लड़कर पचास से साठ जीतना है। वह भी उस समय जब पार्टी के विधायकों की निष्ठा पर हमेशा ही सवाल उठ रहे हों। साथ ही राकांपा में शरद पवार जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को चुनौती देने की कोई हिम्मत दिखा रहा हो।राज्य की राजनीति में हमेशा ही महत्वाकांक्षी माने जाने वाले अजित पवार ने कभी किसी मुकाम पर 'संतोष' जैसा शब्द अपने शब्दकोश में नहीं रखा। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी मंजिलों को लगातार हासिल किया। किंतु उनका राजनीतिक उनवान हमेशा उनके चाचा शरद पवार के नाम पर आया। उनकी प्रगति चाचा ने लिखी और उनकी सीमाएं भी चाचा ने तय कीं। चाचा ने हर सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री तक का पद दिलवाया। इस पर भी भतीजे ने एक सुबह भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के साथ मिलकर सरकार बना ली।

हालांकि सरकार अधिक दिन नहीं चली। बावजूद इसके जब दूसरी बार शिवसेना के साथ सरकार का गठन हुआ तो उसमें भी उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद मिला। इससे पहले भी जब वर्ष 2014 में भाजपा-शिवसेना की सरकार बनी, तब भी उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया था। किंतु वर्ष 2019 में बनी ठाकरे सरकार के वर्ष 2022 में गिरने के

बाद अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षा को शिंदे सरकार में शामिल हो कर पूरा किया। इस कोशिश में उन्होंने अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर 38 विधायकों को अपने पक्ष में किया। अब भविष्य की चुनौती विधानसभा चुनाव है, जिसमें विधायकों की संख्या बढ़ने पर ही कोई भी गठबंधन महत्व देगा। दरअसल अजित पवार ने चाचा शरद पवार के साथ रहते हुए हमेशा दूसरे स्थान पर ही खुद को पाया। इसीलिए जब मई 2023 में उनके समक्ष एक मौका शरद पवार के इस्तीफे के रूप में आया तो तुरंत उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर कमान संभालते हुए खुद को खड़ा किया। मगर वह दांव बेकार गया। पार्टी शरद पवार के नेतृत्व में ही खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा जोखिम भरा कदम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में शामिल होने का उठाया। इससे राकांपा में बड़ी फूट हुई। बड़ी संख्या में विधायक और सांसद उनके साथ आ गए। किंतु इसका अधिक असर राकांपा के मूल भाग, जो आस्था के साथ शरद पवार के साथ था, पर नहीं पड़ा।

इसके विपरीत सहानुभूति चाचा पवार के साथ अधिक बन गई, जिसका प्रमाण लोकसभा चुनाव ने दे दिया। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा दस सीटों पर चुनाव लड़कर आठ सीटें जीत ले गई, जबकि अजित पवार की राकांपा पांच सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक ही सीट पा सकी। उसे 3.6 प्रतिशत मत मिले। यहीं से शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने अजित पवार की राकांपा को सीधे तौर पर चुनौती देना आरंभ किया। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने अनेक अवसरों पर अजित पवार की पार्टी पर सवाल खड़े किए। अनेक विधायकों की वापसी की बात कही, जिसकी पुष्टि शरद पवार ने इस रूप में की कि विधायक उनकी बजाय पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल के संपर्क में हैं।

इसी बीच, राकांपा अजित पवार गुट के प्रमुख नेता छगन भुजबल के पार्टी छोड़ने की हवा उड़ी। हालांकि स्वयं भुजबल ने खबरों का खंडन किया। मगर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेताओं पर टिप्पणी कर भुजबल ने पार्टी के लिए नया खतरा मोल ले लिया। इससे पार्टी में अंदरूनी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार में एक भी मंत्री पद नहीं मिलना पहले ही चिंता का बड़ा कारण है।

उसके समाधान के लिए भाजपा दलीय क्षमता के पैमाने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब विधान परिषद चुनाव की जीत के बाद अजित पवार को विधानसभा चुनाव का सामना करना है। वह भी तब जब एक साल में सफलता कम और असफलता अधिक हाथ लगने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का मनोबल बढ़ाए रखना है। जिस तरह शिवसेना शिंदे गुट के अनेक नेता शिवसेना ठाकरे गुट पर तीखे हमले करते हैं, उस तरह राकांपा अजित पवार गुट का कोई भी नेता राकांपा शरद पवार गुट पर हमले करता भी नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ राकांपा शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले हों या विधायक रोहित पवार, दोनों राकांपा अजित पवार गुट पर हमले करते ही रहते हैं।

भाजपा के हलकों में अजित पवार को लेकर चर्चाएं चलती ही रहती हैं। पिछले दिनों एक बैठक में विधायक नवाब मलिक के शामिल होने पर विवाद उठ गया था। इस स्थिति में अजित पवार का राज्य सरकार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना, विधानसभा चुनाव तक अपने विधायकों को एकजुट रखना और भाजपा के साथ मोलभाव करने की स्थिति में रहना गंभीर चुनौती है। यदि इनसे मुकाबला सहजता से निपट नहीं पाया तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आगे स्थितियां अधर में अटकती जाएंगी। फिलहाल तो दबाव बनाने की स्थिति भी नहीं है। लिहाजा अपनी सीमाओं में चलते रहना वक्त की जरूरत है। अब चाचा का साथ नहीं, बल्कि चाचा के साथ मुकाबला है।

अकाली दल बादल के लिए कांग्रेस अछूती नहीं रहेगी

इकबाल सिंह चन्नी

कांग्रेस के बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल, जिसे आज अकाली दल बादल के नाम से जाना जाता है, के बीच विभाजन सामने आने के बाद अकाली दल बादल विद्रोही नेताओं को भाजपा के समर्थक के रूप में पेश करके खुद यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह सिख सिद्धांतों की एकमात्र संरक्षक पार्टी है और विद्रोही पार्टी अध्यक्ष के इस्तीफे को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल बादल इस समय भाजपा को कांग्रेस से भी बड़ा सिखों का दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रहा है। अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेताओं के हालिया बयानों से भी यह संकेत मिलता है कि अकाली दल बादल के लिए भाजपा और कांग्रेस एक समान हैं।

शिरोमणि अकाली दल का गठन 14 दिसंबर 1920 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक टास्क फोर्स के रूप में किया गया था, कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर, अकाली दल ने हमेशा कांग्रेस को सिख विरोधी माना है और अकाली दल को कभी-कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एस.जी.पी.सी. की मुख्य मांगों के लिए संघर्ष करना और सिखों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना था। इस काम के लिए कभी-कभी अकाली दल को कई अंग्रेजों और कई बार कांग्रेस के साथ लड़ाई लडनी पड़ी मगर अकाली दल अपना मंतव्य पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब भी रहा।

अकाली दल की स्थापना के समय 20वीं सदी की शुरूआत में ही अकाली दल ने कई गुरुद्वारा साहिब को महंतों से आजाद करवाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ कई शांतमयी संघर्ष किए जिनमें 1920 में स्यालकोट में स्थित गुरुद्वारा बाबे दी बेर को करतार सिंह

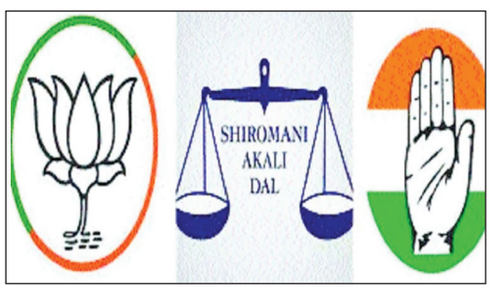

झब्बर के नेतृत्व में महंत हरनाम सिंह की विधवा से आजाद करवाना, 28 जून 1920 को करतार सिंह झब्बर के नेतृत्व में ही हरिमंदिर साहिब को महंतों से आजाद करवाना, गुरुद्वारा पंजा साहिब को महंत मिट्ठा सिंह के कब्जे से मुक्त करवाना, चूहड़ काना स्थित गुरुद्वारा सच्चा सौदा, दरबार साहिब तरनतारन जहां पर काबिज महंतों ने लड़कियों के डांस, तंबाकू सेवन करना शुरू कर दिया था, का कब्जा लेना, 1921 में गुरुद्वारा ननकाना साहिब को महंत नारायण दास से मुक्त करवाना, अक्तूबर 1921 में चाबियों का मोर्चा जीतना, 1922 में गुरु के बाग का मोर्चा जीतना, 1923 में जैतो का मोर्चा लगाना और 1925 में सिख गुरुद्वारा बिल पास करवाना मुख्य तौर पर शामिल हैं।

1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद भी अकाली दल को कई संघर्ष करने पड़े तथा कांग्रेस की सरकारों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा जिनमें केंद्र सरकार की ओर से सिखों को अम्बाला से आगे न बसने देने की कार्रवाई, भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनाने से इंकार करना, पंजाब के जल के मामले में पंजाब के साथ नाइंसाफी करना, आप्रेशन ब्ल्यू स्टार और दिल्ली में सिख कत्लेआम और दोषियों की हिमायत करना मुख्य तौर पर शामिल है। इन कारणों के कारण अकाली दल हमेशा ही कांग्रेस को सिखों की दुश्मन पार्टी के तौर पर पेश करता रहा है। मगर अब अकाली दल भाजपा के साथ संबंध तोडने के बाद से भाजपा को ही सिखों का दुश्मन करार देने लग पड़ा है। बेशक भाजपा ने सिखों के हितों के लिए कई प्रयास भी किए हैं मगर अकाली दल इन प्रयासों का सेहरा भाजपा को देने के लिए तैयार नहीं है। अकाली दल बादल के नेता अपनी पार्टी में पड़ी फूट के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार बताते आ रहे हैं और बागी अकाली नेताओं को भाजपा समर्थक बता रहे हैं।

इसके जवाब में विद्रोही अकाली जिन्होंने अकाली दल सुधार लहर चलाने का फैसला किया है, भी इसी तरह की शैली में जवाब दे रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल पर उनके साथी खुद या भाजपा के साथ समझौता करने के लिए जोर लगाते रहे हैं। मगर जब भाजपा ने इंकार कर दिया तो हम पर बिना वजह दोष लगाए जा रहे हैं। यह एक अजीब स्थिति है क्योंकि ये सभी अकाली नेता करीब 25 साल तक भाजपा गठबंधन में रहे और किसान आंदोलन के कारण अकाली दल को भाजपा के साथ रिश्ता तोडना पड़ा। इस गुटबाजी के कारण अकाली दल बादल अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए हर प्रयत्न करने के लिए सोच रहा है और अकाली दल के कई बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि अकाली दल किसी के साथ भी समझौता कर सकता है। यहां तक कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह झुंदा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान यहां तक कह दिया कि सिख गुरुओं ने सिखों के दुश्मन औरंगजेब के बेटे के साथ और महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। आज के हालात में अकाली दल अपने एजैंडे को लेकरकिसी दुश्मन के साथ समझौता कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अकाली दल के लिए कांग्रेस अब अछूत नहीं रहेगी।

समाज और कानून एक-दूसरे के पूरक लेकिन...

पूरन चंद सरीन

हमारे देश में लगभग साढ़े 1200 कानून हैं और हर बार संसद में नए कानून बनते रहते हैं। इसी प्रकार राज्यों में भी होता है। इन कानूनों, नियमों, प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि नागरिकों का जीवन आसान होगा और वे कभी भी जरूरत पडने पर इनके अंतर्गत न्याय की गुहार लगा सकते हैं। भारत अनेक संगतियों यानी अच्छी बातों और उनके सामने अनेक विसंगतियों यानी खराब और विरोधी विचारों, परंपराओं तथा मान्यताओं से भरा देश है। यह धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, रहन-सहन की बात नहीं है, वह तो विविधता लिए हुए ही हैं, एकता की तलाश करने की भावना से जुड़े हैं। कोई भी अपनी संस्कृति या धरोहर त्यागना तो दूर, तनिक बदलना भी नहीं चाहता। इन पर आंच आती दिखाई देती है तो रक्षा के लिए प्रदर्शन, हिंसा और अनेक असामाजिक गतिविधियां होती हैं। पुलिस, प्रशासन भी यथासंभव कानून के अनुसार कार्रवाई करता दिखाई देता है। प्रश्न यह है कि जब सब कुछ कानून में तय है तो क्यों उनमें कोई खामी यानी लूपहोल खोजने लगता है ताकि जो वह चाहता है, कर सके और कानून के उल्लंघन का ठीकरा भी उसके माथे पर न फोड़ा जा सके और लगे कि सब कुछ नियम और कानून के अनुसार हुआ है? यहीं से शुरू होता है रिश्वत यानी सुविधा शुल्क का खेल जो भ्रष्ट तरीके अपनाए बिना पूरा नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि कानून इस बात की गारंटी नहीं हैं कि उनके मुताबिक चलकर आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें इस बात की दावत दी जाती है कि आपको काम कराना है और हमें करना है तो हमारी मेज की दराज खुली है, उसमें भेंट दीजिए और बाकी हम पर छोड़ दीजिए। यदि कोई इतनी-सी बात न समझे तो फिर वह नियमानुसार काम कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खाए, अपना समय गंवाए और कुछ न हो तो अपने भाग्य को दोष देकर घर बैठ जाए।हमारे देश में लगभग हर बात के लिए नियम और कानून हैं, जैसे कि सड़क पर चलना, गाड़ी चलाना, किसी भी साधन से यात्रा, खरीदना, बेचना, उपभोक्ता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, वन और वन्य जीव तथा पर्यावरण रक्षण, खेतीबाड़ी, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, मानवाधिकार, प्राकृतिक या मानवीय आपदा, मतलब यह कि एक लंबी सूची है जो इसका भ्रम पैदा करती है कि यदि कुछ गलत होता है तो कानून, पुलिस, प्रशासन तथा अंत में सरकार तो है न जो हमें सुरक्षा देने के लिए मौजूद है। विडंबना यह है कि समय, काल, परिस्थिति और व्यक्ति की हैसियत के अनुसार ही न्याय और अन्याय की परिभाषा तय होती है। इसके अतिरिक्त यह तय करने में ही दिन, महीने और वर्ष निकल जाते हैं कि जिस तथाकथित अपराध के लिए कोई कार्रवाई की गई है, उसका स्रोत क्या है? हालांकि हरेक बात के लिए समय सीमा निर्धारित है परंतु न तो कोई कानून है और न ही किसी दंडाधिकारी में इस बात की उत्सुकता दिखाई देती है कि निर्धारित समय नामक प्रावधान का पालन हो। यह बेबुनियाद तर्क दिया जाता है कि चाहे कितने भी अपराधी बच जाएं पर एक भी निर्दोष को सजा न हो। यहीं से पक्षपात की शुरूआत होती है, जोड़-तोड़ की प्रक्रिया चलने लगती है, बच निकलने के प्रयास होते हैं और कानून के हाथ चाहे जितने भी लंबे बताए जाएं, उसके अंधे होने का कवच अपराधी को सुरक्षा प्रदान कर देता है।

मैं मिल रहे रिस्पॉन्स से थोड़ी चकित हूं: दीपिका

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने हाल ही में रिलीज होने के साथ ही दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दीपिका पादुकोण इस फ्यूचरिस्टिक एपिक फिल्म में लीड रोल में हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है।
जब से कल्कि 2898 एडी थिएटर्स में रिलीज हुई है, तब से दर्शक दीपिका को फिल्म की जान कह रहे हैं। फैंस और क्रिटिक्स दीपिका की फिल्म में दमदार प्रेजेंस और जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों से मिल रहे प्यार पर एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन दिया है, उनके साथ शेयर किए गए वीडियो में उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। दीपिका ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने फिल्म को मिल रिस्पॉन्स पर अपना रिएक्शन शेयर की है। सामने आए वीडियो में उन्होंने कहा है, 'मुझे नहीं पता कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए। मैं मिल रहे रिस्पॉन्स से थोड़ी चकित हूं। इसी वीडियो में रणवीर भी नजर आ रहे हैं। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म देखने के बाद वह पूरी तरह से निशब्द हैं।
रणवीर ने वीडियो में कहा, 'इस तरह की फ़िल्म देखना वाकई हैरान करने वाला है, जिसमें उनका किरदार प्रेगनेंट है और वह खुद भी प्रेगनेंट हैं और ऐसा लगता है कि ये क्या ही हो रहा है?' बता दें कि इस वीडियो में फैंस का प्यार देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि दीपिका पादुकोण सिर्फ 'कल्कि 2898 एडी' का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे इसका सार हैं। 'कल्कि 2898 एडी' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। बता दें कि प्रभास-दीपिका पादुकोण की 'कल्कि 2898 एडी' रिलीज के बाद से ही लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म में दीपिका, प्रभास और अमिताभ समेत सभी स्टारकास्ट के काम को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म दूसरे हफ्ते में भी कमाई कर रही है।

सुहाना संग वेकेशन एंजॉय कर रहे शाहरुख खान

न्यूयार्क में सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। सुहाना खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की, जिनमें वह बेहद प्यारी लग रहीं हैं। पहली तस्वीर में सुहाना कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं।
उन्होंने बालों को खुला रखा है और न्यूड मेकअप किया हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में सुहाना खान कैमरे से शीशे के सामने खड़े होकर फोटो लेती नजर आ रहीं हैं। इस दौरान सुहाना ने न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरत फोटो भी शेयर की। उन्होंने अपनी क्लोजअप फोटो भी साझा किया। इसके अलावा, एक फोटो में वह मिरर सेल्फी लेती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रिंटिड ड्रेस पहनी हुई हैं और कानों में गोल्डन ईयररिंग्स डाले हुए हैं। सुहाना खान की इन फोटो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। हाल ही में सुहाना खान की एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें वह पापा शाहरुख के साथ शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। फोटो में दोनों कैश काउंटर पर बिल देते नजर आ रहे हैं।
लुक की बात करें तो सुहाना ने फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई हैं, वहीं शाहरुख खान ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए। वर्क फ्रंट की बात करें तो सुहाना ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म किंग में नजर आएंगी, जिसे सुजॉय घोष डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सिद्धार्थ आनंद की मार्फ्लिक्स एंटरटेनमेंट मिलकर करेंगे।

सारा ने पहना मोतियों से सजा लहंगा

बीते दिनों जाम नगर में हुए अंबानी परिवार के प्री-इवेंट्स में एक्ट्रेस सारा अली खान ने मोतियों से सजा व्हाइट फिश-कट लहंगा पहना था। इस लहंगे पर मोतियों का डिटेलिंग में वर्क था। ब्लाउज हाल्टर नेक था और उस पर भी मोती ही मोती जड़े थे। इसके साथ सारा ने सिंपल से स्टड ईयररिंग्स पहने थे। सारा की लुक को फैंस ने सिंपल एंड स्टनिंग कहा था। जामनगर के लास्ट इवेंट में सारा ने चुड़ीदार के साथ कलियों वाला शॉर्ट लैंथ अनारकली सूट पहना था। मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया ये सूट रॉयल समय की याद दिलवा रहा था। सूटपर जरदोजी गोल्ड बॉर्डर था और सूट की स्लीव्स कफ स्टाइल में थी। इसके साथ सारा ने ग्रीन कलर की चांद बाली स्टाइल ईयररिंग्स और मांग-टीका लगाया था। सारा पर सिर्फ ट्रडीशनल ही नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट भी बहुत सुदंर लगते हैं। उनकी एनिमल प्रिंट वाली ये ड्रेस देखिए। सारा ने फोटोशूट का ये वीडियो अपनी इंस्टा पेज पर अपलोड किया है। इसके साथ सारा ने एक स्लिक सा नेकपीस और मैचिंग रिंग पहनी थी। इस बार के अंबानी फंक्शंस में सारा की दो लुक सामने आई है।
हल्दी सेरेमनी पर सारा ने बंजारा स्टाइल मल्टीकलर लहंगा पहना था। लहंगे पर मिरर और धागे का खूबसूरत वर्क था। इसके साथ सारा ने मल्टीकलर नेकलेस, कंगन और रिंग पहनी थी जब कि कानों को खाली ही छोड़ा था। इससे पहले सारा अली खान ने अनंत राधिका की संगीत नाइट पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया गोल्डन फिशकट लहंगा पहना था जिसके साथ मैचिंग फूल स्लीव ब्लाउज था। बता दें कि सारा अली खान अपने चुलबुले अंदाज के लिए फैंस की चहेती हैं वहीं लोगों को उनका फैशन भी खूब पसंद आता है। इन दिनों सारा अली खान अंबानी फंक्शंस अटैंड कर रही हैं। दोनों ही लुक्स में वह देसी दीवा बनी और फैंस का प्यार भी मिला इससे पहले हुए प्री-वैडिंग सेलिब्रेशन में भी सारा अली खान का लुक सुर्खियों में रहा था चलिए आपको सारा की बेस्ट आउटफिट्स दिखाते हैं।

यह फिल्म मेरी मां के लिए मेरी सबसे खास: सनी सिंह

हाल ही में एक्टर सनी सिंह ने अपनी मां के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव के बारे में खुलकर बात की। चर्चा में सनी ने भावुक होते हुए कहा कि अपकमिंग फिल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाब मेरी मां के लिए मेरी सबसे खास और महत्वपूर्ण फिल्म है। रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने इसका हर सीन देखा था। उन्होंने कहा कि जब भी फिल्म के बारे में बात होती थी तो वह उत्साहित हो जाती थीं, वह पूछती थी कि फिल्म कब शुरू हो रही है? या तुम कब जा रहे हो? एक्टर ने कहा कि उनकी मां इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थीं। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। लव (रंजन) सर भी जानते हैं कि यही वजह है कि मैं इस फिल्म से भावनात्मक रूप से इतना जुड़ा हुआ हूं। इसके अलावा, इस फिल्म में अन्य कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए अपने परिवार के साथ काम करने जैसा था।सनी की बात करें तो उन्होंने कसौटी जिंदगी की से टेलीविजन पर डेब्यू किया था। बाद में वह शकुंतला सीरीज में भी नजर आए। उन्होंने 2010 में शाहिद कपूर अभिनीत पाठशाला से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें दिल तो बच्चा है जी, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, दे दे प्यार दे, उजड़ा चमन, जय मम्मी दी और आदिपुरुष जैसी फिल्मों में देखा गया। बता दें कि सिमरप्रीत सिंह द्वारा निर्देशित वाइल्ड वाइल्ड पंजाब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो अपने दोस्तों के साथ ब्रेकअप रोड ट्रिप पर जाता है। फिल्म में वरुण शर्मा, जस्सी गिल, मनजोत सिंह और पत्रलेखा भी हैं। यह 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

गेम चेंजर की शूटिंग हो गई है पूरी: राम चरण

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग पूरी हो चुकी है। पैन इंडिया स्टार राम चरण ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरों का एक कोलाज साझा कर दी। राम चरण को पहली तस्वीर में हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर शूटिंग खत्म होने के बाद की है।

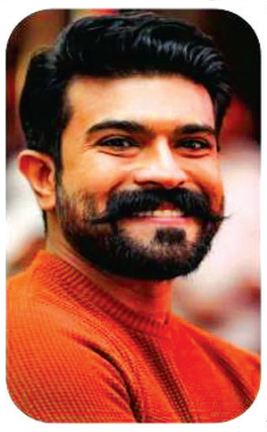

एक्टर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, खेल बदलने वाला है! गेम चेंजर की शूटिंग पूरी हो गई है... अब सिनेमाघरों में मिलते हैं।राम चरण के इस पोस्ट को सामंथा रूथ प्रभु और आलिम हकीम जैसी हस्तियों ने लाइक किया है। यह एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, राम चरण इसके फाइनल शेड्यूल की शूटिंग आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में कर रहे थे। इसका निर्देशन एस. शंकर ने किया है। वहीं निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने किया है। इस फिल्म में राम चरण के साथ कियारा आडवाणी, जयराम, अंजलि, एसजे सूर्या, श्रीकांत, सुनील, समुथिरकानी और नासर लीड रोल में हैं। गेम चेंजर में एक्टर तिहरे किरदार यानि ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। गेम चेंजर की रिलीजि डेट का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह पांच भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जाएगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो, राम चरण जल्द फिल्म गेम चेंजर के अलावा आरसी 16 और आरसी 17 में भी नजर आएंगे। आरसी 16 एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें वह एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के अपोजिट नजर आएंगे। इसका निर्देशन बुच्ची बाबू करेंगे। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार भी दिखाई देंगे। फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार कर लिया है। आरसी 17 की घोषणा राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली के मौके पर की थी।

इंडस्ट्री में इन दिनों महंगाई बढ़ रही है: करण जौहर

बालीवुड फिल्ममेकर करण जौहर का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों महंगाई बढ़ रही है। हिंदी सिनेमा में करीब 10 एक्टर्स हैं और वो सभी सूरज, चांद और धरती मांग रहे हैं। इसलिए आप उन्हें पैसा देते हैं। फिर फिल्म के लिए पैसा देते हैं और फिर दूसरे खर्चे भी आते हैं। लेकिन आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पाती।
करण जौहर ने आगे कहा- जो फिल्म स्टार्स 35 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। वो 3.5 करोड़ रुपये से ओपनिंग कर रहे हैं। यह गणित कैसे काम कर रहा है? मालूम नहीं। फिर भी आपको फिल्में बनाते रहना चाहिए और कंटेंट तैयार करना चाहिए क्योंकि आपको पेट भी पालना है। अगर जवान-पठान जैसी फिल्में सफल रहीं तो क्या हमें सिर्फ एक्शन फिल्में ही बनाना चाहिए? हर कोई उसी तरफ भाग रहा है। लेकिन अचानक से अगर लव स्टोरी काम कर जाती है तो ऐसा लगता है कि हम बिना सिर वाली मुर्गियों की तरह इधर-उधर भाग रहे हैं।
इसके अलावा करण जौहर ने कहा कि दर्शकों की पसंद बहुत निश्चित हो गई है। वह एक खास तरह का सिनेमा चाहते हैं और अगर आप एक निर्माता के तौर पर एक खास नंबर चाहते हैं तो आपकी फिल्म को ए, बी और सी सेंटर पर भी परफॉर्म करना होगा। सिर्फ मल्टीप्लेक्स ही काफी नहीं होंगे। बता दें कि फिल्ममेकर करण जौहर ने बहुत सारी फिल्में बनाई है, जिनमें से कुछ फिल्मों को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। हाल ही में करण ने मोटी फीस मांगने वाले स्टार्स को लेकर बात की है, जिनकी फिल्में आधा भी नहीं कमा पाती हैं।

नाटू नाटू को पुरस्कार मिलने से 'उत्साहित' नहीं थे कीरवानी

फिल्म आरआरआर का गाना नाटू नाटू भारत में रिलीज होने पर काफी हिट रहा और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म की टीम को दुनिया भर से प्यार मिला। हालाँकि, इस गाने को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पूरा देश खुशी से झूम उठा है, लेकिन संगीतकार कीरवानी ने हमेशा इस बारे में अपना संयम बनाए रखा है।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह गाना उनका 'सर्वश्रेष्ठ' काम नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें वो पहचान बहुत देर से मिली जिसके वो हकदार थे, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए, देर से या जल्दी, वैश्विक पहचान एक ऐसे गाने को मिली है जो मेरा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। लेकिन, जब पहचान मिलनी होती है, तो वो किसी न किसी तरह से, किसी भी कोने से आ ही जाती है। लेकिन देर? कभी-कभी आपको लगता है कि देर हो गई है क्योंकि आपका जीवनकाल तय है, इसे ही देर या जल्दी कहा जाता है, जब आपका जीवनकाल तय नहीं होता है, तो यह तब आता है जब इसे आना होता है। ऑस्कर जीतने के बाद भारत लौटने पर, कीरवानी ने माना कि वह इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिलने से 'उत्साहित' भी नहीं थे।
उन्होंने इस गाने को लाने के लिए दिवंगत रामोजी राव को श्रेय दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, शुरू में मैं ऑस्कर के लिए नामांकित होने को लेकर उत्साहित नहीं था। लेकिन, जब मैं रामोजी राव से मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पुरस्कार घर ले आऊँ। मैंने सोचा, अगर वे ऑस्कर को इतना महत्व दे रहे हैं, तो मुझे इसे जीतना ही होगा। मुझे लगा कि उस समय पुरस्कार का महत्व था और पुरस्कार की घोषणा से कुछ सेकंड पहले मैं नर्वस भी था। मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए।
हिंदी में एम.एम. क्रीम के नाम से मशहूर कीरवानी ने अजय देवगन, तब्बू अभिनीत औरों में कहां दम था के लिए संगीत तैयार किया है और अनुपम खेर अभिनीत तन्वी द ग्रेट पर काम कर रहे हैं। तेलुगु में, वे चिरंजीवी अभिनीत विश्वम्भर और पवन कल्याण अभिनीत हरि हर वीरा मल्लू के लिए धुन तैयार कर रहे हैं। बता दें कि संगीतकार एमएम कीरवानी ने एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू से वैश्विक पहचान हासिल की और उन्हें गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर से सम्मानित किया गया। फिल्म के मुख्य कलाकारों जूनियर एनटीआर और राम चरण पर फिल्माया गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

उपचुनाव में 'इंडिया' गठबंधन ने मारी बाजी

नईदिल्ली। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 'इंडिया' गठबंधन को शानदार जीत मिली है, तो बीजेपी को केवल दो सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि बिहार के रुपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली। 13 सीटों में 'इंडिया' गठबंधन को 10 में जीत मिली है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पंजाब की एक, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखंड की दो, पश्चिम बंगाल की चार, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर मतदान हुआ था। 'इंडिया' गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। पश्चिम बंगाल की चार सीटों पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपना दबदबा कायम रखा। ममता की पार्टी ने सभी चार सीटें जीत ली हैं। रायगंज से कृष्णा कल्याणी को जीत मिली, तो रणघाट दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी ने चुनाव जीत लिया।

झारखंड के सीएम सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात

नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सोरेन पहली बार सोनिया से मिलने पहुंचे। सोरेन ने कहा कि भाजपा न्यायपालिका को अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए मिलने आया हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। भाजपा के संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के सवाल पर सोरेन ने कहा कि भारत के लोग बहुत सहनशील और सहयोगी होते हैं। वह बहुत सहते हैं और जब वे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वोट के जरिये अपनी बात रखते हैं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि केजरीवाल को जल्द जमानत मिल जाएगी।

संविधान हत्या दिवस का नीतीश की पार्टी का समर्थन

पटना। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि, सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। हालांकि, सबको इस बात की भी उत्सुकता थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का इस पर क्या रुख रहता है। इसी को लेकर अब जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल जाने का भी मौका मिला। इससे उनके परिवार वालों को भी परेशानी हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जेडीयू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले का स्वागत करती है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का एक काला दिन है और हमें खुशी है कि इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। कांग्रेस पर तंज सकते हुए उन्होंने कहा कि जब जयराम रमेश की पार्टी जश्न मना रही थी, हम सभी सलाखों के पीछे थे और उन्हें दर्द का अंदाजा नहीं था।

आपातकाल के बचाव में उतरे शिवसेना यूबीटी नेता राउत

नई दिल्ली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले का बचाव किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का एलान किया। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। संजय राउत ने कहा आपातकाल लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं और लोग भी आपातकाल को भूल चुके हैं। देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया? कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुलेआम एलान किया गया, हमारे जवान, सेना को कहा गया कि वह सरकार के आदेश न मानें...ऐसी परिस्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। देश में कुछ लोग बम बना रहे थे और विभिन्न स्थानों पर बम फट रहे थे।

आप नेता मोहिंदर भगत ने जालंधर पश्चिम सीट जीती

चंडीगढ़। पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राहत भरी खबर है। लोकसभा चुनाव में आप को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 13 में से 3 सीट पर मात्र जीत मिली थी। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की शनिवार को जारी मतगणना में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को 37323 वोट से मात दी। कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। आप प्रत्याशी को 55246 वोट मिले। भाजपा को 17921 मत से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर रहीं और उन्हें 16,757 वोट मिले। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) उम्मीदवार सुरजीत कौर को 1,242 वोट मिले जबकि बसपा उम्मीदवार बिंदर कुमार को 734 मत मिले। आप विधायक के तौर पर अंगुराल के इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। वह मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे।

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में किया संशोधन

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के नियमों में संशोधन किया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की अटकलों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अधिक शक्ति मिल गई है। इसका मतलब यह है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी निर्वाचित सरकार के पास आंतरिक सुरक्षा, स्थानांतरण, अभियोजन और अटॉर्नी-जनरल सहित सरकारी वकीलों की नियुक्ति सहित महत्वपूर्ण मामलों में सीमित शक्तियाँ होंगी। अधिसूचना में कहा गया है, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, एआईएस और एसीबी के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी

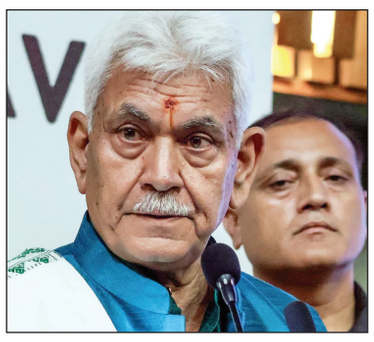

प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों का विभाग मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अदालती कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। अधिसूचना के अनुसार, अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 2019 में संशोधन किया है। 5 जुलाई को, सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अमरनाथ यात्रा के बाद होंगे, जो 19 अगस्त को समाप्त होगी। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक की और क्षेत्र के नेताओं से चुनाव की तैयारी करने को कहा, सूत्रों ने कहा।

इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और कामकाज के नियमों में बदलाव इस बात का एक और संकेत है कि चुनाव के बाद के परिदृश्य में शासन मॉडल के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में क्या होने वाला है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसी प्रमुख पार्टियों ने केंद्र की कार्रवाई को एक निर्वाचित सरकार को नगर परिषद में बदलने का प्रयास करार दिया।

उपराज्यपाल की बढ़ी ताकत तो भड़की कांग्रेस

■ **जम्मू-कश्मीर के साथ लगातार जारी है मोदी सरकार का विश्वासघात**

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पुलिस और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां सौंपने के कदम को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करना चाहती है और अगर राज्य का दर्जा बहाल भी हो गया तो नवनिर्वाचित राज्य सरकार को उपराज्यपाल की दया पर निर्भर रखना चाहती है।

इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर के साथ मोदी सरकार का विश्वासघात लगातार जारी है! उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत नियमों में संशोधन करके एलजी को अधिक शक्तियां देने वाली नई धाराओं को शामिल करने के केवल दो अर्थ हैं-

1) मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करना चाहती है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। 2) भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाए, यह नवनिर्वाचित राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति को दबाकर उसे उपराज्यपाल की दया पर निर्भर रखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए इसे मोदी सरकार में प्रतिदिन जारी संविधान हत्या दिवस का एक और उदाहरण बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह कदम जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस, आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर निर्णय लेने और विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए अधिक शक्तियां देता है।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने पलट दी पूरी बाजी

कांग्रेस तो छोड़िए सपा और एआईएमआईएम के विधायकों ने भी एनडीए के लिए कर दिया वोट

मुंबई। महाराष्ट्र में विधान परिषद के नतीजे सामने आते ही सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। विधानपरिषद के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। एनडीए के महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीट अपने नाम कर ली। इंडिया गठबंधन के तीन प्रत्याशियों में से सिर्फ दो ही जीत सके हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उसके कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन के बाद फुल कॉन्फिडेंस में आई एमवीए को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। माना जाता है कि कांग्रेस के छह विधायकों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, जबकि शरद-पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के नेताओं के अजित गुट के विधायकों के संपर्क में होने के दावे को भी इस प्रदर्शन ने हवा-हवाई साबित कर दिया है। अजित के नेतृत्व वाली राकांपा के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, जो लोकसभा चुनावों के बाद बैकफुट पर थी, जिसमें उसने जिन चार सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से उसने सिर्फ एक सीट जीती थी, जो मैदान में सभी छह प्रमुख दलों में से सबसे कम थी।

अजित ने अपने साथ राकांपा विधायकों पर अपनी पकड़ साबित की तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने पक्ष में मौजूद शिवसेना विधायकों पर अपनी पकड़ कायम कर ली। विडंबना यह है कि लोकसभा नतीजों के बाद जिस कांग्रेस के पास मुस्कुराने की सबसे ज्यादा वजहें थीं, जिसने बीजेपी (9) से भी ज्यादा सीटें (13) हासिल की थीं। लेकिन शुक्रवार को उसे सबसे बड़ा झटका लगा। निर्दलियों के समर्थन से भाजपा के पास 111 विधायकों की ताकत थी, जिससे उसके पांच उम्मीदवारों को जीत मिली। शिंदे सेना के पास सीएम सहित 38 विधायक हैं, और उसने प्रहार जनशक्ति पार्टी के दो विधायकों और सात निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिससे उसकी ताकत 47 हो गई। उसके दो उम्मीदवार जीते, यह दर्शाता है कि उसे दो अतिरिक्त वोट मिले। अजित की एनसीपी के पास 39 विधायक हैं और उसने तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उसके दो उम्मीदवार जीते, जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी को पांच और वोट मिले।

आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (1), राष्ट्रीय समाज पार्टी (1), निर्दलीय और यहां तक ??कि समाजवादी पार्टी (2 विधायक) और एआईएमआईएम (2) जैसे छोटे दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मतदान किया। यह स्वीकार करते हुए कि कांग्रेस विधायकों ने दूसरे पक्ष को वोट दिया था, पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमने उन छह विधायकों की पहचान की है जिन्होंने व्हिप के बावजूद क्रॉस वोटिंग की थी। एक विस्तृत रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी और सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पटोले ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में कार्रवाई के लिए किसी समिति के फैसले का इंतजार नहीं करेगी।

कांग्रेस के लिए अधिक चिंता की बात यह है कि उसके 37 विधायकों में से चार के अजित के नेतृत्व वाली राकांपा के संपर्क में होने की खबरें थीं। सूत्रों के मुताबिक, जिन दो अतिरिक्त विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वे कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं, जो अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। विधान परिषद चुनाव नतीजे कांग्रेस के अलावा एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के लिए भी झटका है। अपने भतीजे अजीत को एक और झटका देने की कोशिश के रूप में देखे जाने वाले शरद पवार ने एमवीए की ओर से तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके दांव पर लगी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। एमवीए के पास केवल दो को चुनने के लिए संख्या बल था, लेकिन उन्होंने एनसीपी (एसपी) समर्थित पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के तीसरे, जयंत पाटिल को मैदान में उतारा। उत्तरार्द्ध - लोकसभा चुनावों में लड़ी गई 10 सीटों में से आठ पर जीत हासिल करने के बाद उच्च स्तर पर था - यह दावा कर रहा था कि अजीत गुट के 18 विधायक पार्टी के संपर्क में थे। अंत में अजित की ओर से एक भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है।

उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा का था, जिसने विधान परिषद चुनावों के संख्यात्मक खेल के प्रबंधन में खुद को फिर से माहिर साबित कर दिया। पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए सभी पांच नेताओं ने जीत हासिल की और इस प्रक्रिया में लोकसभा चुनावों के झटके के बाद भाजपा को जो संतुलन बनाने की उम्मीद थी, वह हासिल किया।

खेल
प्रमुख समाचार

विम्बलडन फाइनल में कार्लोस अल्काराज का सामना जोकोविच से

लंदन। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर विम्बलडन फाइनल में प्रवेश कर लिया जहां उनका सामना नोवाक जोकोविच से होगा। अपना 21वां जन्मदिन मनाने से कुछ महीने दूर अल्काराज अगर जीत जाते हैं तो उनका लगातार दूसरा विम्बलडन और चौथा ग्रैंडस्लैम खिताब होगा। उन्होंने मेदवेदेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया । जीत के बाद उन्होंने कहा ,'' लग रहा है कि अब मैं नया नहीं हूं । मुझे पता है कि फाइनल में कैसा लगता है। मैं पहले भी खेल चुका हूं और उसी प्रदर्शन को दोहराऊंगा।''

पिछली बार भी फाइनल में उनका सामना जोकोविच से ही था। जोकोविच ने 25वीं वरीयता प्राप्त इटली के लोरेंजो मुसेत्ती को 6-4, 7-6, 6-4 से हराया। जोकोविच के 2014 और 2015 में रोजर फेडरर को हराने के बाद से पहली बार लगातार दो फाइनल समान प्रतिद्वंद्वियों के बीच होगा। जोकोविच इस सत्र में किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच सके हैं। जून में उन्होंने दाहिने घुटने का आपरेशन भी कराया। उन्हें यहां क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला था जब उनके प्रतिद्वंद्वी एलेक्स डि मिनौर ने कूल्हे की चोट के कारण नाम वापिस ले लिया। एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले और ग्रास, क्ले और हार्ड तीनों कोर्ट पर खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अल्काराज अब 22 वर्ष की उम्र से पहले दो विम्बलडन खिताब जीतने वाले बोरिस बेकर और ब्योर्न बोर्ग के बाद तीसरे खिलाड़ी बनने से एक जीत दूर है। जोकोविच के नाम सबसे ज्यादा बार ग्रैंडस्लैम फाइनल खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। जोकोविच 37वीं बार किसी ग्रैंडस्लैम के खिताबी मुकाबले में पहुंचे हैं। उनके बाद सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम खेलने के मामले में रोजर फेडरर हैं जिन्होंने अपने करियर में 31 बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में जगह बनाई, जबकि स्पेन के राफेल नडाल 30 बार ग्रैंडस्लैम का खिताबी मुकाबला खेल चुके हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

नेट डायरेक्ट कलेक्शन बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रू. पर पंहुचा

नईदिल्ली। चालू वित्त वर्ष में अब तक नेट डायरेक्ट कलेक्शन 19.54 प्रतिशत बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से अधिक एडवांस टैक्स के भुगतान के कारण इसमें वृद्धि हुई है। अग्रिम कर की पहली किस्त (15 जून तक) 27.34 प्रतिशत बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स और 34,470 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 11 जुलाई, 2024 तक 5,74,357 करोड़ रुपये के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 2,10,274 करोड़ रुपये का सीआईटी और 3,46,036 करोड़ रुपये का पीआईटी शामिल है। वहीं, सिक्योरिटीज ट्रांसकेशन टैक्स ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16,634 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

बीएसएनएल को एमटीएनएल का संचालन सौंपने पर विचार

नईदिल्ली। सरकार एक समझौते के जरिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का संचालन बीएसएनएल को सौंपने के विकल्प पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सरकार विलय की जगह इस विकल्प पर विचार कर रही है। इस पर अंतिम फैसला एक महीने में लिए जाने की संभावना है। सूत्र ने बताया कि कर्ज में डूबी एमटीएनएल का संचालन एक समझौते के जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एमटीएनएल के भारी कर्ज को देखते हुए बीएसएनएल के साथ विलय अनुकूल विकल्प नहीं है। फैसला लिए जाने के बाद प्रस्ताव सचिवों की समिति के सामने रखा जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी।

बीएसई में रॉकेट बन गया टीसीएस का स्टॉक

नईदिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद भारत में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का स्टॉक बंबई स्टॉक एक्सचेंज में रॉकेट बन गया। इसी का नतीजा रहा कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को करीब सात फीसदी तक चढ़ गया। इसी के साथ टीसीएस का मार्केट कैप में 94,866.26 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। टीसीएस के शेयर में जोरदार बढ़ोतरी की वजह से शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स एक नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ और एनएसई निफ्टी भी ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस ने गुरुवार 11 जुलाई 2024 को कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में नेट प्रॉफिट 8.7 प्रतिशत बढ़कर 12,040 करोड़ रुपये रहा। इसी दौरान टीसीएस का राजस्व 5.4% की वृद्धि के साथ 62,613 करोड़ रुपये हो गया।

जल्द ही दूसरे देशों को सुखोई लड़ाकू विमान बेचेगा भारत

नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमानों का निर्यात के लिए उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य के स्वामित्व वाली एचएएल विभिन्न वैश्विक रक्षा बलों के साथ बातचीत भी कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल अपनी नासिक की यूनिट में इन लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए सक्रिय बातचीत कर रहा है। सुखोई जेट का मूल निर्माता रूस दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए इस प्रयास का समर्थन करने के लिए सहमत हुआ है। प्रधानमंत्री की हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और दोनों देशों ने मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तमंत्री को भी देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे मुद्रा स्फीति तो कम होगी ही परंतु साथ ही अर्थव्यवस्था में विकास की दर भी और तेज होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ते रहने से विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। परंतु यदि वस्तुओं की मांग में कमी करते हुए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास होंगे तो उत्पादों की मांग में कमी होने के चलते उत्पादों का निर्माण कम होने लगेगा, विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां कम होंगी एवं देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। मांग में कमी करने के प्रयास सम्बंधी सोच ही अमानवीय है।

इसी प्रकार, प्राचीन भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे, इन कृषि उत्पादों के साथ ही इन कुटीर एवं लघु उद्योगों में निर्मित उत्पाद भी बेचे जाते थे। अत: ग्रामीण इलाकों से शहरों की पलायन नहीं होता था तथा नागरिकों को रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध हो जाते थे। आज की परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो सकें।

जनता पर करों के बोझ को कम करने के सम्बंध में भी विचार होना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कर सम्बंधी नीति का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को जनता पर करों का बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है। अर्थात, जनता को करों का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने बजट में भी आवश्यक वस्तुओं पर लागू करों की दरों को कम करने के प्रयास होने चाहिए। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों को भी करों में छूट देकर कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी उत्पादों को खरीदने के क्षमता बढ़े। इससे अंतत: अर्थव्यवस्था को ही लाभ होता है। मध्यमवर्गीय परिवारों की खरीद की क्षमता बढ़ने से विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का चक्र और अधिक तेजी से घूमने लगता है। यदि किसी देश में अधिक से अधिक आर्थिक व्यवहार औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र भी तेज गति से घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में करों के संग्रहण में भी वृद्धि दर्ज होती है। अत: कई बार करों की दरों में कमी किए जाने के बावजूद कर संग्रहण अधिक राशि का होने लगता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि माननीया वित्त मंत्री जी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के रूप में एक अच्छा मौका है कि भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप आर्थिक नीतियों को लागू कर पूरे विश्व को पूर्व में अति सफल रहे भारतीय आर्थिक दर्शन के सम्बंध में संदेश दिया जा सकता है।

पांच लाख के इनामी समेत पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सरकार की नीति से प्रभावित होकर उठाया कदम

सुकमा। सुकमा में लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और छत्तीसगढ़ सरकार की नीति से प्रभावित होकर पांच लाख के इनामी नक्सली सहित पांच नक्सलियों ने सुकमा के नक्सल ऑपरेशन कार्यालय पहुंच पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मामले की पुष्टि करते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की ''छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति'' एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ''नियद नेल्ला नार '' योजना से प्रभावित तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 02 महिला नक्सली सहित कुल 05 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। इनामी नक्सली सागर उर्फ दूधी कोसा को समर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में रेंज फिल्ड टीम डीआईजी ऑफिस कोंटा (आरएफटी) एवं 212, 217 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा, नक्सली मुचाकी कोसा को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 223 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा एवं शेष नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में नक्सल सेल आसूचना शाखा तथा डीआरजी सुकमा का विशेष प्रयास रहा। उपरोक्त सभी प्रतिबंधित नक्सल संगठन में जुड़कर विभिन्न नक्सली गतिविधियों जैसे पुलिस गस्त पार्टी की रेकी कर हमला करना, पुलिस पार्टी के आने-जाने वाले मार्गो में स्पाईक लगाना, मुख्य मार्गों को खोदकर अवरूद्ध करना, शासन-प्रशासन के विरूद्ध में नक्सली पर्चा-पाम्पलेट लगाना आदि घटनाओं में शामिल रहे है।

गौरतलब है की आत्मा समर्पित नक्सलियों में 500000 के इनामी नक्सली सागर उर्फ दूधी कोसा पिता देवा निवासी दंतेशपुरम (गालीकोण्डा (ओड़िशा) एरिया कमेटी कमाण्डर ने भी पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया है ।

16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों ने पंचायत प्रतिनिधियों से की चर्चा

बस्तर में तेजी से समग्र विकास का खींचा गया खाका

आईजी और कलेक्टर ने बस्तर संभाग की परिस्थितियां, चुनौतियां, संभावना और अपेक्षाओं से आयोग को कराया अवगत

रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर में किया वृक्षारोपण16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्यों ने पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए पंचायतों के तेजी से समग्र विकास का खांका खींचा। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

पंचायत प्रतिनिधियों के सुझावों पर वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री पनगढ़िया ने कहा कि 16 वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगा द्य इस अवधि को ध्यान में रख कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप हमें विकास की आगामी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां जो सुझाव दिए गए हैं, वे सभी वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं तथा इन पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जनसरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात की गई, जिनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि 15 वें वित्त आयोग अन्तर्गत 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर आवंटन जारी किया जाता है। बस्तर जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आश्रित ग्राम एवं पारा दूर-दूर तक फैले हुए हैं, इस कारण क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए 16 वें वित्त आयोग अन्तर्गत 70 प्रतिशत जनसंख्या एवं 30 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर आबंटन प्रदाय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा हमारा बस्तर संस्कृति से भरपूर है,चाहे देवगुड़ी हो. मेला, मंडई हो. बस्तर में इसकी अत्यधिक मान्यता है। इसे ध्यान में रखते हुए देवगुड़ी, मेला, मंडई एवं खेलकूद क्षेत्र के लिए भी आबंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

बस्तर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने कहा बस्तर में पेसा एक्ट लागू होने के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। 16 वें वित्त आयोग अन्तर्गत जनसंख्या, क्षेत्रफल के साथ-साथ नक्सल एवं पेसा जिले को अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने की बात कही। साथ ही बस्तर की अधिकांश आबादी इन वन क्षेत्र में रहती है तथा अधिकांश आदिवासियों के आय का मुख्य स्त्रोत लघु वनोपज होता है। लघु वनोपज की सामग्री को वैल्यू एडिशन कर सह उत्पाद की श्रेणी में लाने की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त आबंटन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ ही अन्य पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बस्तर जिले में पथरीली एवं पहाड़ी जमीन को देखते हुए कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता के सेक्टर की बाध्यता को समाप्त कर अन्य 09 थीम से सेक्टर चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करने, ऑनलाईन भुगतान प्रणाली के सरलीकरण, किसानों को सामूहिक फेंसिंग एवं नलकूप की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता देने, ग्राम पंचायतों में अधोसंरचनाओं के विकास हेतु आश्रित ग्रामों के आधार पर आबंटन प्रदान करने के संबंध में सुझाव दिए गए।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अंचल के जनजाति संस्कृति के आस्था केन्द्र देवगुड़ी, मातागुड़ी, मृतक स्मारकों का संरक्षण करने, पर्यटन स्थलों में सुविधाओं का विकास करने के संबंध में भी सुझाव दिए गए। इसके साथ ही आधुनिक सूचना तकनीक के माध्यम से लोगों को त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के सुझाव दिए भी गए।

पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने इस दौरान वामपंथियों से हुई जनहानि के साथ ही क्षेत्र के विकास में पड़े विपरीत प्रभाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके साथ ही इस समस्या के निदान के लिए बनाई गई रणनीतियों के संबंध में भी बताया तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत संरचना के लिए तेजी से कार्य किए जाने हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता के संबंध में आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी।

कलेक्टर विजय दयाराम के. ने इस अवसर पर बस्तर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वामपंथी उग्रवाद, तकनीकी, प्रशासनिक, आर्थिक भौगोलिक चुनौतियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने पंचायतों के आय के रुप में वित्त आयोग के अनुदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इसके साथ ही विगत वित्त आयोगों की राशि से बस्तर में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में जानकारी भी दी तथा बस्तर में तेजी से विकास हेतु मानव संसाधन, सूचना तकनीकी उपकरण, अंचल के लिए विशेष सहायता तथा जनजातीय कल्याण के कार्य को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया।

केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रजेंटेशन पूरी तरह से स्थानीय आधारभूत जरुरतों पर केंद्रित कर तैयार किया गया था। प्रजेंटेशन से बस्तर को समझने के साथ ही विकास के आगे बढ़ाने वाले कदमों की जानकारी भी मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने आउटकम डाटा को भी जिला स्तर में संग्रहण संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने इसके साथ ही आयोग के अध्ययन भ्रमण हेतु बेहतर व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इस दौरान जिला प्रशासन तथा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सहभागिता को बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया सहित उपस्थित सदस्यों ने कलेक्टोरेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। यहां आम, कदम, खम्हार आदि पौधे लगाए गए।

इस दौरान आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ.सौम्यकांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेन्द्र सिंह, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ ने राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांटा बासन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपना अग्रणी राजस्थान के संकल्प. के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट और कांटा बासन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए करने की छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति दे दी है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है।

बैगाओं के मौत का कारण साय सरकार की नाकामीः बघेल

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कवर्धा के डायरिया प्रभावित गांव पहुंचे. भूपेश बघेल ने उल्टी-दस्त से आदिवासियों की मौत को लेकर साय सरकार को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही कहा कि बैगाओं की मौत का कारण साय सरकार की नाकामी है.इस दौरान पूर्व सीएम ने स्वाथ्य विभाग और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने ग्राम सोनवाही में 5 बैगा आदिवासियों की उल्टी दस्त से मौत को जिला प्रशासन द्वारा छुपाने की कोशिश का आरोप लगाया है. दरअसल, कबीरधाम जिला के बैगा बाहुल्य क्षेत्र सोनवाही गांव में बीते तीन दिनों में उल्टी-दस्त से दो बैगा आदिवासियों की मौत हो गई थी. मौत की सूचना के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल तेज बारिश में डायरिया प्रभावित गांव सोनवाही पहुंचे. साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की. इसके साथ ही वनांचल क्षेत्र के ग्राम झलमला के समुदियिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से मरीजों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान पूर्व सीएम ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की बात कही. सोनवाही गांव में उल्टी दस्त से मौत होने के बाद स्वास्थ्य कैम्प लगाया गया. शुक्रवार को 94 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें 25 ग्रामीण मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के घर में मच्छर दानी वितरण किए. वह भी उन्हीं लोगों को मच्छरदानी दी गई, जिनके घर में मरीज मिले है, जबकि सोनवाही गांव के सभी घरों में मच्छर दानी वितरण करना चाहिए. प्रशासन को बारिश से पहले शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ग्रामीण मजबूरी में कुआं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. क्षेत्र में अस्पताल तो बनाया गया है, लेकिन अस्पताल में डाक्टर नहीं हो तो इलाज कैसे होगा?

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

आज भाजपा की तरफ से मतदाताओं का सम्मान

भाटापारा। केंद्र में फिर से सरकार बनने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं का सम्मान करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 14 जुलाई रविवार को भाटापारा विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनन्दन समारोह का आयोजन गोदड़ी धाम रेलवे अंडरब्रिज के पास दोपहर 1.30 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी एवं उपाध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़ शिवरतन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां, संकल्प पत्र, विकसित भारत के विषय एवं प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विकास कार्यों के पर विस्तृत रूप से बताया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं, प्रबुद्धजनों सहित प्रत्येक बूथ से 10-10 मतदाताओं को आमंत्रित किया गया है।

सुको में होगा 29 जुलाई से विशेष लोक अदालत का आयोजन

रायपुर। भारत के उच्चतम न्यायालय की ओर से 29 जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों के ऐसे आपसी राजीनामा के प्रकरण जिनका निराकरण विशेष अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है, उन्हें निराकृत किया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, राज्यों की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जर्नल, लॉ सेकेटरी सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर पर प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा की संभावनाएं है, उनका चिन्हांकन और सूचीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनोज कुमार पिंगुआ, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

निगम चुनावः वार्ड परिसीमन का प्रकाशन 17 को

रायपुर। वार्ड परिसीमन का प्रकाशन 17 जुलाई को होगा और परिसीमन पर आपत्ति पेश करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई तक हैं। बता दें कि विधानसभा, लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नवंबर-दिसम्बर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर निकायों में वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डा. बसवराजु एस. ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। 2011 की जनसंख्या 2.55 करोड़ बताई गई है। वर्तमान में आबादी तीन करोड़ से अधिक है। प्रदेश में 184 निकाय है,वहीं इनमें 169 निकायों में चुनाव होंगे। बाकी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2025 में पूरा होगा। परिसीमन कार्य को इसलिए गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाता सूची शीघ्र तैयार किया जा सके।

मप्र निर्मित 22 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

राजनादगांव। अवैध शराब को पकड़ने में कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। तस्कर मध्यप्रदेश निर्मित शराब को कार से मध्यप्रदेश के बैतूल से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की और ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश के बैतूल से राजनांदगांव के रास्ते जगदलपुर स्कोडा कार में शराब तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने कन्हारपुरी बाईपास के समीप घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा, जिसमें पुलिस को 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मामले को लेकर राजनांदगांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि मध्यप्रदेश के बैतूल से जगदलपुर शराब तस्करी करने वाले राजनांदगांव के पेन्ड्री निवासी आरोपी शेख अमीर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शराब को बैतूल मध्यप्रदेश से जगदलपुर ले जाना बताया गया, जिसकी जांच की जा रही है। मध्यप्रदेश निर्मित 22 पेटी अंग्रेजी शराब की कीमती 1 लाख 26 हजार 500 रूपये आंकी गई है।

छत्तीसगढ़ की डॉक्टर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक दम्पति के जुड़वा बच्चों का जन्म होते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी. इस खुशी का कारण डॉ. विनीता धुर्वे का अनोखा रिकॉर्ड था. जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. विनीता ने महज ढाई साल में 100 जुड़वां बच्चों की डिलीवरी कराकर देश में एक रिकॉर्ड बनाया है. हॉस्पिटल के स्टाफ भी डॉक्टर विनीता को जुड़वा बच्चों के डिलीवरी कराने का स्पेशलिस्ट मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जुड़वा केस में सबसे अधिक नॉर्मल डिलवरी कराई है. बताया जा रहा है कि भिलाई के कैलाश नगर निवासी शेख फैयाज की पत्नी बुशरा परवीन ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है. डॉ. विनीता धुर्वे दुर्ग जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में गायनेकोलाजिस्ट हैं. शुक्रवार को उन्होंने फिर दो जुड़वां बच्चियों की डिलीवरी कराई है. ये उनकी जुड़वां बच्चों की 100वीं डिलीवरी थी. खास बात ये है कि उन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराई है वहीं, 6, 480 प्रसव सीजेरियन ऑपरेशन से करा चुकी हैं.

विवादों को आगे बढ़ाने की बजाय सुलझाने का हो प्रयास

विवादों को आगे बढ़ाने की बजाय सुलझाने का हो प्रयासःभादुड़ी

रायपुर। न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर और कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने आज कोरबा में नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य व कोशिश है कि आपसी झगड़े और विवाद में जल्द से जल्द विराम लगे। लोक अदालत से दोनों पार्टी संतुष्ट होकर घर जाते हैं। कई ऐसे मामले होते है जिसमें प्रकरण दाखिल होने के साथ जीत-हार की संभावना रहती है। इसके विरूद्ध हाईकोट, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है और एक वकील तथा न्यायाधीश के रूप में मेरा अनुभव है कि मुकदमा लड़ना कितना खर्चीला होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विवादी है, मुकदमें में उलझा है तो दिमाग में हमेंशा तनाव बना रहता है, जिससे तबीयत भी खराब होती है। आप जो उन्नति करना चाहते है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कही न कही रोक लग जाता है।

न्यायाधीश भादुड़ी ने कहा कि जब तक समाज है, इसमें झगड़ा होते रहेगा, क्योंकि यह समाज के साथ ही चलने वाली बात है। आप फोटोग्राफी में देखे होंगे कि निगेटिव्ह से ही पॉजीटिव फोटो बनता है। सोसायटी में भी निगेटिव्ह चीजें रहती है, जब तक लोग है, कुछ न कुछ आपसी विवाद भी साथ रहेगा। लोक अदालत का मंच एक प्रयास है कि विवादों को कम करने के सुलझने योग्य प्रकरणों को सुलझाने की। न्यायाधिपति श्री भादुड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रकरणों को सुलझाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य कई बड़े राज्यों से आगे है, इसके लिए न्यायाधीश, अधिवक्तागण तथा पक्षकार बधाई के पात्र है।

न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि विवाद खत्म होने पर उन्नति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। अपना ध्यान किसी कार्य में केंद्रित किया जा सकता है। आप देखेंगे कि विवादी में ईगो, छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े विवाद होते हैं। ऐसे विवादों को सुलझाने में आप प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई प्रकरण चलाना है तो लम्बा चलता ही रहेगा। इसलिए दो कदम आप चलेंगे तो दो कदम वे भी चलेंगे। वकील और जज की कोशिश रहती है कि विवाद जल्दी समाप्त हो। लोक अदालत में लोग एक दूसरे से गले मिलकर जाएं। कुछ प्रकरणों में बहुत समय लग जाता है। अपील होने के बाद निर्णय आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोई चीज समय पर न मिले तो उसकी अहयिमत खत्म हो जाती है। इसलिए समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। विवादों को अनावश्यक बढ़ावा देने की बजाय अधिकतम प्रकरणों को सुलझाना चाहिए। लोक अदालत का आयोजन विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से ही की गई है। आप सभी इसका लाभ उठाइये। उन्होंने सभी को लोक अदालत के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कोरबा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र साहू, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्री जयदीप गर्ग, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.